सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
भोपाल
शनिवार, 16 मई, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 253, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews


प्रसंगवश

# महंगा सोना : क्या भारतीय वाकई कम कर देंगे खरीदारी?

**रजनीश कुमार**

भारत ने सोने और चांदी पर इम्पोर्ट टैरिफ़ यानी आयात शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15% कर दिया है। तीन फ़ीसदी जीएसटी को शामिल करने पर कुल आयात शुल्क 9.18% से बढ़कर 18.45% हो जाएगा। यानी पहले 100 रुपए का आयातित सोना क़रीब 9.18 रुपये के टैक्स के साथ भारत आता था। अब उसी आयात पर लगभग 18.45 रुपये का टैक्स लगेगा। यानी प्रभावी आयात शुल्क का बोझ 100% से अधिक बढ़ गया है।

यह क़दम ऐसे समय में उठाया गया है, जब क़ीमती धातुओं का आयात तेज़ी से बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने लगभग 72 अरब डॉलर का सोना आयात किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक था। वहीं चांदी का आयात 12 अरब डॉलर से अधिक का रहा था, जिसमें सालाना 150% की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई।

दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) का मानना है कि यह वृद्धि भारत-यूएई कॉम्परहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीइपीए) के तहत वहाँ से आने वाले कीमती धातु आयात के गणित को भी काफ़ी बदल देगी। सीइपीए के तहत भारत ने मई 2022 से शुरू होकर 10 सालों में चांदी पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर शून्य करने पर सहमति दी थी। वर्तमान में यूएई से आने वाली चांदी पर रियायती शुल्क सात फ़ीसदी है।

अब भारत ने सामान्य आयात शुल्क को 15% कर दिया है, ऐसे में शुल्क का अंतर आठ प्रतिशत तक बढ़ गया है। इससे दुबई के जरिए आयात करना सस्ता हो गया है। जीटीआरआई के निदेशक अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि यह अंतर हर साल और बढ़ेगा क्योंकि सीईपीए के तहत टैरिफ़ 2031 तक घटकर शून्य हो जाएगा। यूएई से सोने के आयात को भी समझौते के तहत ख़ास रियायत हासिल है। भारत ने टैरिफ रेट कोटा प्रणाली के तहत दुबई से सोने के आयात पर मोस्ट-फेवर्ड-नेशन की दर से एक प्रतिशत कम शुल्क की अनुमति दी थी। यह कोटा 2022 में 120 टन प्रतिवर्ष से शुरू हुआ था और 2027 तक बढ़कर 200 टन हो जाएगा, जो भारत के वार्षिक सोना आयात का लगभग एक-चौथाई है। नई एमएफएन शुल्क व्यवस्था के तहत जहां सामान्य प्रभावी शुल्क 15% हो गया है, वहीं यूएई कोटा के तहत आने वाला सोना 14% शुल्क पर आएगा। 'आयात शुल्क के बढ़ते अंतर से वैश्विक बुलियन व्यापार का बड़ा हिस्सा दुबई के ज़रिए आने की संभावना बढ़ सकती है, जबकि यूएई ख़ुद सोना या चांदी का खनन करने वाला देश नहीं है।'

'यूएई के साथ जो समझौता हुआ है, उसमें लिखा है कि जो भी भारत का टैरिफ़ होगा, उससे एक प्रतिशत कम में दुबई से सोना आएगा। यानी बाक़ी देशों से सोना लाने पर 15 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगेगा लेकिन दुबई से लाने पर 14 प्रतिशत का ही टैरिफ़ लगेगा। सोना इतना महंगा हो गया है कि एक फ़ीसदी टैरिफ़ कम होना भी बड़ी रियायत होगी। ऐसे में दुबई से सोना लेने की होड़ लग सकती है।'

चाँदी के मामले में अजय श्रीवास्तव कहते हैं, 'सिल्वर में तो और ज़्यादा क़ीमतों में फ़र्क़ होगा। सरकार ने 15 फ़ीसदी टैरिफ़ सिल्वर के ऊपर लगाया है। लेकिन दुबई से सिल्वर के लिए कहा है कि 2031 तक ज़ीरो पर्सेंट टैरिफ़ होगा। टैरिफ़ कम होते-होते आज की तारीख़ में सात फ़ीसदी रह गया है। यानी 15 प्रतिशत बाक़ी देशों से टैरिफ़ और दुबई से केवल सात प्रतिशत। यानी आठ प्रतिशत टैरिफ़ की छूट मिलेगी। भारतीय दुबई से सिल्वर ख़रीदना पसंद करेंगे। भारत यूएई से किसी एग्रीमेंट से अचानक बाहर नहीं सकता है।'

मोदी सरकार ने आयात शुल्क में बढ़ोतरी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बुलियन बाज़ार भारत में मांग कम करने के उद्देश्य से की है। यह क़दम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने नागरिकों से सोना ख़रीदने और ग़ैर-ज़रूरी विदेशी यात्राओं से बचने को कहा था ताकि रुपये को सहारा दिया जा सके।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत, पर्शियन गल्फ़ में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से महंगाई की चपेट में है। सोना भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। बचत, विवाह और धार्मिक त्योहारों में इसकी अहम भूमिका है। भारत सोने की मांग आयात से पूरी करता है और पिछले साल 710 टन सोने का आयात हुआ था।

ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास अभी 690 अरब डॉलर का फॉरेक्स है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने कच्चे तेल के आयात के लिए 174 अरब डॉलर ख़र्च किए थे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर 116 अरब डॉलर। तीसरे नंबर पर सोने का आयात था और जिसकी क़ीमत 72 अरब डॉलर थी। बढ़ते आयात बिलों के कारण विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ा है। इससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया और भारतीय रिज़र्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा।

कंसल्टेंसी फर्म मेटल्स फोकस के प्रमुख सलाहकार चिराग शेठ ने कहा कि शादियों के लिए सोना ख़रीदना सरकारी फ़ैसले के बावजूद जारी रहेगा। इस अवधि में लोग क़ीमतें स्थिर होने का इंतज़ार करते हुए सोना ख़रीदना रोक सकते हैं।'

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर रहे अरुण कुमार कहते हैं कि 'जब रुपया कमज़ोर रहेगा तो लोग निवेश के लिए सोना ही ख़रीदेंगे। आयात शुल्क बढ़ाने का सीधा फ़ायदा यूएई को होगा और सोने की तस्करी भी बढ़ेगी।

ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल का मानना है कि सरकार ने गोल्ड पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी डॉलर बचाने के लिए नहीं बल्कि टैरिफ़ से पैसे कमाने के लिए की है। सिंघल कहते हैं, '2023 में भारत ने 743 टन सोने का आयात किया था और तब टैरिफ़ 15 फ़ीसदी ही था। पिछले साल गोल्ड पर टैरिफ़ छह प्रतिशत था और आयात 710 टन था। ऐसे में कोई कैसे मान ले कि आयात शुल्क बढ़ जाने से सोने का आयात कम हो जाएगा।'

एक मई तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690.7 अरब डॉलर रह गया है, जो एक महीने से अधिक समय का सबसे निचला स्तर है। हालांकि यह भंडार अब भी 10 से 11 महीनों के आयात बिल को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

भारत के प्रमुख अंग्रेज़ी अख़बार इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम ने जब सोने की ख़रीद एक साल तक नहीं करने की अपील की उसके बाद पूरे भारत में लोगों ने घबराहट में ख़रीदारी शुरू कर दी। पिछले दो दिनों में शादी के गहनों की बिक्री औसत दैनिक बिक्री की तुलना में 15% से 20% बढ़ गई है। '

**(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित रिपोर्ट के संपादित अंश)**

## शरद की सुबह

ख़तरे के भी निशान से आगे निकल गया
दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया

जुगनू को इक फ़क़ीर की ऐसी दुआ लगी
सूरज के ख़ानदान से आगे निकल गया

तंक़ीद करने वाले बहुत पीछे रह गए
मैं उनके दरमियान से आगे निकल गया

दुनिया लगी हुई है इसी छान-बीन में
मैं कैसे आसमान से आगे निकल गया

दिल टूटने के बाद तिरा ख़ानुमा ख़राब
परियों की दास्तान से आगे निकल गया

संदल तुम्हारे लम्स का महका जो एक शाम
ख़ुशबू में ज़ाफ़रान से आगे निकल गया

उर्दू ने शोहरतों को मेरी पर लगा दिए
मैं मादरी ज़ुबान से आगे निकल गया।

- शाहिद अंजुम

# धार भोजशाला को हाई कोर्ट ने मां वाग्देवी का मंदिर माना

## हिंदू पक्ष की मांगें स्वीकार, हाई कोर्ट का फैसला



**इंदौर।** भोजशाला को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद में शुक्रवार को बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप देवी वाग्देवी सरस्वती के मंदिर के रूप में स्थापित होता है। अदालत ने यह भी माना कि इस स्थान पर हिंदू समाज की पूजा-अर्चना की परंपरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि यह स्थान परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा केंद्र रहा है, जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता था। न्यायालय ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका का निराकरण करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला मंदिर तथा संस्कृत शिक्षण से जुड़े प्रबंधन और संचालन को लेकर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

**अदालत ने यह कहा-** न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का विवादित परिसर 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक की श्रेणी में है और यह 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित क्षेत्र माना जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसर का समग्र प्रशासन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन ही रहेगा। फैसले में कहा गया कि केंद्र सरकार और पुरातत्व विभाग भोजशाला मंदिर के संरक्षण, संस्कृत शिक्षा और व्यवस्थापन को लेकर आगे की रूपरेखा तय करेंगे। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि उपलब्ध प्रमाण इस स्थान के मूल स्वरूप को मंदिर से जोड़ते हैं।

### कैसे शुरू हुआ मामला

भोजशाला को लेकर विवाद लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच चला आ रहा है। हिंदू समाज का दावा है कि यह स्थल मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला की मस्जिद बताता रहा है। विशेष रूप से वसंत पंचमी के अवसर पर पूजा-अर्चना और नमाज को लेकर यहां कई बार तनाव की स्थिति बनती रही। यह कानूनी लड़ाई वर्ष 2022 में उस समय नए दौर में पहुंची जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की। इसके बाद मामले में लगातार सुनवाई हुई।

**सर्वे में क्या मिला-** मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया था। करीब 98 दिनों तक चले सर्वेक्षण के बाद 15 जुलाई 2024 को विस्तृत प्रतिवेदन अदालत में प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि परिसर में 106 स्तंभ और 82 स्थापत्य अवशेष मिले, जिन्हें पुराने मंदिरों का हिस्सा माना गया और बाद में मस्जिद निर्माण में उपयोग किए जाने की बात कही गई। कई स्तंभों पर देवी-देवताओं, शेर और हाथियों की आकृतियां मिलीं, जिनके क्षतिग्रस्त होने के संकेत भी रिपोर्ट में दर्ज किए गए। जांच में 10वीं और 11वीं शताब्दी के परमारकालीन शिलालेख तथा बाद के काल के सिक्के भी मिले। दो हजार से अधिक पन्नों की रिपोर्ट में इस स्थल के मूल रूप से हिंदू मंदिर होने की संभावना व्यक्त की गई।

**हिंदू पक्ष की प्रमुख मांगें-** याचिका में हिंदू समाज को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार देने की मांग की गई थी। इसके अलावा परिसर में नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने, केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाकर प्रबंधन संभालने तथा मां सरस्वती की प्रतिमा की निरंतर पूजा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। याचिका में यह मांग भी शामिल थी कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाकर भोजशाला में स्थापित किया जाए।

### फैसले से पहले कड़ी चौकसी

फैसले को देखते हुए धार जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने धारा 163 लागू कर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी थी। किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया। पुलिस ने सामाजिक माध्यमों पर भड़काऊ टिप्पणियों की निगरानी तेज कर दी थी। साथ ही पेट्रोल और डीजल की बोतलों में बिक्री पर भी विशेष नजर रखी जा रही थी।

### वसंत पंचमी पर भी बड़ा आदेश

इस मामले में पहले भी महत्वपूर्ण आदेश सामने आ चुके हैं। 23 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा-अर्चना की अनुमति दी थी। इसके बाद 6 अप्रैल 2026 से इंदौर खंडपीठ में लगातार सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली। अदालत ने उसी दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार 15 मई को सुनाया गया।

### मुस्लिमों को नमाज का अधिकार नहीं

हाई कोर्ट ने एएसआई का 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताते रहे मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने सरकार से मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने को कहा है।

### मुस्लिम और जैन पक्ष जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

धार शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और शोभा मेनन ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। अब फैसले की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वहीं जैन समाज की ओर से पैरवी कर रहीं एडवोकेट प्रीति जैन ने कहा कि सुनवाई के दौरान यह दावा किया गया था कि तीर्थंकरों की मूर्तियों के अवशेष आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं और उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जैन समाज भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

### सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर

भोजशाला विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह विशेन की ओर से अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने कैविएट दाखिल की। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर किसी भी अपील पर हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।

# गुरुदेव के आशीर्वाद से ही सनातन और सत्य मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा मिलती है: मुख्यमंत्री

## जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में सिंहस्थ जैसा नजारा, स्व अनुशासन से अनुशासित लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब

**उज्जैन/भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में जय गुरुदेव आश्रम में गुरुदेव महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया और उनके अमृत प्रवचनों का श्रवण किया। गुरुदेव श्री उमाकांत जी महाराज ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सदा ऐसे ही समाज की सेवा में लगे रहे और सत्य, सनातन, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जन सेवा करते रहें। आज आप अपने कार्यो से जनता के प्यारे बन गए है।



सनातन धर्म में मान्यता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें यह मानव जीवन मिलता है। इस मानव जीवन को सही तरीके से जीने का जो मार्ग आपके द्वारा बताया जाता है उससे जीवन सरल और संयमित होकर जीने का मार्ग मिल जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा की महाराज जी की कृपा से हमने प्रदेश में गौशालाओं को बनाने और संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुदेव के निर्देश पर मंच से ही गुरुदेव के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरुदेव की उज्जैन में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरुवर को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं ईश्वर को देख लिया हो, यह आश्रम परमात्मा का घर है, परमात्मा का आशीर्वाद है कि हमें गुरुवर का आशीर्वाद उनके स्वरूप में मिल रहा है और जीवन में सत्य कार्य करने का जो मार्गदर्शन हमें गुरुवर के चरणों से मिलता है उसे जीवन जीने का नया मार्ग हमें प्राप्त होता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाराज जी का आशीर्वाद चिर काल तक हम सभी को मिलता रहे और आनंद के साथ जीवन का यापन करें।

उज्जैन सहित अन्य धार्मिक नगरों में भी शराब बंदी के लागू की है और प्रदेश में उज्जैन ओंकारेश्वर, महेश्वर दतिया, पीतांबरा पीठ, सलकनपुर, ओरछा, चित्रकूट सहित 19 नगर में शराबबंदी का आदेश भगवत कृपा से ही हो पाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 में उज्जैन को हम मेट्रो सिटी के साथ-साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी स्थापित कर पाएंगे। उज्जैन अब धार्मिक नगरी के साथ उत्सव की नगरी भी हो गई है गुरुदेव की कृपा से अब हम हर जिले में गीता भवन बना रहे हैं, जहां पर भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशों का वाचन और आध्यात्मिक अध्ययन भी हो सकेगा। भगवान श्रीकृष्ण के अनुयायी होते हुए हम सब गोपालन को भी अपना रहे हैं और गोपालक परिवारों को आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं।

# पेट्रोल-डीजल 3-3 रुपए महंगे हुए, नई कीमतें लागू

● दिल्ली में पेट्रोल 97.77 लीटर हुआ, कंपनियों को अभी भी 25-30 रू. प्रति लीटर का घाटा

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। नए दाम आज 15 मई से लागू हो गए हैं। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है।

**इनके बढ़ सकते हैं दाम**

- मालभाड़ा बढ़ेगा
- खेती की लागत बढ़ेगी
- बस-ऑटो का किराया बढ़ेगा।

**2024 से दाम नहीं बदले थे, चुनाव से पहले कटौती हुई थी-** देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्च 2024 से स्थिर बनी हुई थीं। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकार ने कीमतों में 2 प्रति लीटर की कटौती कर जनता को राहत दी थी।

- **बढ़ी कीमतों पर भड़के राहुल गांधी, बोले- गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी-** कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को कहा कि गलती मोदी सरकार करेगी और कीमत जनता चुकाएगी। उन्होंने यह दावा भी किया कि तीन रुपये का झटका आ चुका, बाकी वसूली क़िस्तों में की जाएगी।
- **पेट्रोल-डीजल कीमतों में वृद्धि, कांग्रेस बोली-** चुनाव खत्म, वसूली शुरू, अखिलेश बोले साइकिल ही विकल्प पेट्रोल, डीजल में 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। सरकार पर बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच आम लोगों पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। इस बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है।

# चांदी एक दिन में 19,693, सोना 3,000 रू. सस्ता

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** सोने-चांदी की कीमतों में 15 मई को गिरावट देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, एक किलो चांदी 19,693 रुपए घटकर 2.68 लाख रुपए रह गई, जो गुरुवार को 2.87 लाख रुपए पर थी।

● **डॉलर के मुकाबले रुपया 96.14 पर आया, यह ऑलटाइम लो, महंगाई बढ़ने का खतरा-** रुपया आज 15 मई को डॉलर के मुकाबले 50 पैसे गिरकर पहली बार 96.14 के रिकॉर्ड निचले



स्तर पर आ गया है। इससे पहले गुरुवार को रुपया 95.64 के ऑल टाइम लो पर पहुंचा था। पिछले कुछ दिनों से रुपए में लगातार गिरावट जारी है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c


# सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 16 मई 2026


जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

## उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अस्पताल परिसर के निर्माणाधीन कार्यों का किया निरीक्षण

**भोपाल।** उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने संजय गांधी अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर रीवा में विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन मातृत्व एवं शिशु विंग, सहित कैंसर यूनिट व डॉक्टर्स क्वार्टस के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता कार्य करते हुए समय सीमा में कार्यों के पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस दौरान डीन डॉ. सुनील अग्रवाल उपस्थित रहे।

### उप मुख्यमंत्री ने रीवा शहर के तीन एसटीपी का किया लोकार्पण,जयंती कुंज एसटीपी का होगा जीर्णोद्धार

## सुंदर, स्वच्छ व स्वस्थ रीवा बनाने के लिये सभी कार्य प्राथमिकता से कराये जा रहे हैं : उप मुख्यमंत्री

**भोपाल।** उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि किसी भी शहर आदर्श शहर बनाने के लिये आवश्यक है कि हर घर में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो तथा घर के कचरे व गंदे पानी का निष्पादन किया जाय। रीवा को सुंदर, स्वच्छ व स्वस्थ शहर बनाने के सभी कार्य प्राथमिकता से कराये जा रहे हैं। रीवा के हर घर में मीठा पानी पहुंचाना व घर से निकलने वाले गंदे पानी का निष्पादन करके रीवा आदर्श शहर के मानक को पूरा करेगा। उप मुख्यमंत्री ने रीवा शहर के विकास और स्वच्छता को नई दिशा देने के उद्देश्य से तीन एसटीपी का लोकार्पण किया तथा जयंती कुंज के एसटीपी के जीर्णोद्धार कार्य का भूमिपूजन किया।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जब रीवा छोटा शहर था तब यहाँ की आधी आबादी को खारा पानी मिलता था। रीवा शहर में भूमिगत नालियाँ नही थी। मगर प्रधानमंत्री जी के संकल्प व मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रीवा में हर घर को मीठा पानी दिलाने के लिये 12 टंकियाँ बन रही हैं। भूमिगत नालियाँ बनाई गई हैं तथा घरों से निकलने वाले गंदे पानी को सीवरेज प्लांट तक ले जाकर साफ करने का कार्य कराया जा रहा है। रीवा शहर के आगामी 35 वर्ष के विस्तार व आबादी के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर कार्य किये जा रहे हैं ताकि आने वाले

वर्षों में किसी भी प्रकार की समस्या न आये। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकास व जनोन्मुखी कार्यों को पूरा करना चुनौती है। इसे पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराया जायेगा और रीवा के नागरिकों को महानगर की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बाबाघाट, विवेकानंद एवं बिछिया के एसटीपी के बन जाने से लगभग 25 हजार घरों का गंदा पानी साफ होगा। जयंती कुंज में पूर्व में निर्मित एसटीपी जो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था उसे भी सुधारा जायेगा। शीघ्र ही एजी कालेज के समीप निर्माणाधीन एसटीपी का भी लोकार्पण होगा और संपूर्ण रीवा शहर के घरों का गंदा पानी स्वच्छ होगा तथा रीवा गंदगी मुक्त साफ शहर होगा। साथ ही बीहर नदी भी साफ व स्वच्छ होगी।

इस अवसर पर सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि बीहर नदी में गिरने वाले नालों का पानी अब साफ होकर नदी में जायेगा जिससे नदी साफ होगी व घरों का गंदा पानी भी नहीं बहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के हर घर को शुद्ध पानी दिलाने व गंदे पानी को साफ करने के संकल्प को उप मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपेक्षा की कि रीवा को स्वच्छता में 7 स्टार दिलाने में सहयोग करें ताकि हमारा रीवा भी देश के साफ शहरों की सूची में और ऊपर आ जाय।

### संक्षिप्त समाचार

● बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

## राम मंदिर निर्माण में हमेशा बाधा बनते रहे सपा, बसपा और कांग्रेस

**महराजगंज (एजेंसी)।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की प्रक्रिया बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके व बिना झुके चलती रहेगी। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम जैसे ऐतिहासिक कार्य संभव हुए ।सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां इन कार्यों में हमेशा बाधा बनती रहीं। इसी बाधा को पश्चिम बंगाल की जनता ने हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को महराजगंज के नौतनवा में 208 करोड़ की लागत से 79 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास तथा लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं टूलकिट वितरित करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित रह रहे थे ।

**सीएम योगी ने गन्ना मूल्य भुगतान,3.21 लाख करोड़ सीधे बैंक खातों में भेजे, 36000 करोड़ का कर्ज माफ किया–** उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 3,21,963 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करके इतिहास रचा है। यहां जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। अपने पहले फैसले में किसानों की 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर्जमाफी करने वाली सरकार के निर्देश पर किसानों को समय से गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा रहा है

## मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का आरजी कर, रेप और मर्डर केस में बड़ा एक्शन, पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल समेत तीन आईपीएस अधिकारी सस्पेंड

**कोलकाता (एजेंसी)।** बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बहुचर्चित आरजी कर कांड में शुक्रवार को अब तक की सबसे बड़ी कारवाई की है ।राज्य सचिवालय नवान्न में दोपहर में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों विनीत गोयल (कोलकाता पुलिस के तत्कालीन पुलिस आयुक्त), इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता के निलंबन की घोषणा की। सुवेंदु ने तीनों आइपीएस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।

## मप्र की भाजपा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजाक बना दिया है : जीतू पटवारी

**भोपाल।** मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रशासनिक अराजकता, शिक्षकों के साथ अन्याय और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। सरकार को यह तक नहीं पता कि लाखों कर्मचारी किस विभाग के अंतर्गत आते हैं और उनकी पेंशन की जिम्मेदारी किसकी है।

श्री पटवारी ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 3 लाख शिक्षकों को अपना कर्मचारी मानने से इंकार किया जाना बेहद गंभीर और अमानवीय मामला है। इस निर्णय के कारण लाखों शिक्षकों की पुरानी पेंशन, सेवा सुरक्षा और लगभग 20 वर्षों की वरिष्ठता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों पर सीधा हमला है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था एक क्रूर मज़ाक बन चुकी है। जो शिक्षक वर्षों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, आज वही अपने भविष्य और अधिकारों को लेकर

असुरक्षित हैं। सरकार को तत्काल स्पष्ट करना चाहिए कि इन शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, पेंशन और वरिष्ठता की जिम्मेदारी कौन लेगा।

श्री पटवारी ने कहा कि एक ओर प्रदेश के लाखों युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार नौकरियां समाप्त कर रही है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर 25 लाख से अधिक युवक-युवतियों ने पंजीकरण कराया है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में बेरोजगारी भयावह स्तर पर पहुंच चुकी है। श्री पटवारी ने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय सरकार ने प्रदेश में 1.2 लाख से अधिक पद समाप्त कर दिए। सरकार यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है कि उसके पास वेतन देने के लिए बजट नहीं है। यदि सरकार के पास कर्मचारियों और युवाओं के लिए बजट नहीं है, तो फिर हजारों करोड़ रुपये के कर्ज लेकर इवेंटबाज़ी और प्रचार पर खर्च कैसे किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के तथाकथित रोजगार मेले केवल दिखावा और प्रचार का माध्यम बन चुके हैं। एक लाख से अधिक पद समाप्त कर सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उसे प्रदेश के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय प्रदेश को बेरोजगारी की ओर धकेल रही है।

श्री पटवारी ने मांग की कि सरकार तत्काल शिक्षकों से जुड़े फैसले को वापस ले और सभी शिक्षकों को नियमानुसार पेंशन, सेवा सुरक्षा एवं वरिष्ठता का लाभ सुनिश्चित करे। साथ ही समाप्त किए गए पदों को पुनः बहाल कर नए पद सृजित किए जाएं ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

## सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम

● जज कार पूलिंग करके कोर्ट जाएंगे मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर फैसला

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोर्ट के हर विभाग का स्टाफ दो दिन वर्क फ्रॉम होम पर रहेगा। सभी जज कार पूल करेंगे। रजिस्ट्री से जुड़ा 50 फीसदी स्टाफ भी घर से काम करेगा। सोमवार, शुक्रवार और मिसलेनियस डे (जो दिन पहले से तय नहीं होते) पर लिस्ट मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके अलावा कोर्ट के अन्य वर्किंग डे में भी सुनवाई ऑनलाइन ही की जाएगी।

## भदोही-संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, पत्नी व बेटे को 10-10 साल कैद; बहू को चार साल की सजा

सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत उनकी पत्नी रामलली और बेटे विष्णु मिश्रा को कोर्ट ने 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं उनकी बहू रूपा मिश्रा को चार साल कैद की सजा मिली है। एमपीएमएलए की अदालत ने संपत्ति हड़पने के मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। पूर्व विधायक की पत्नी और उनकी बहू को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ही सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

### गुजरात की लोक-डायरो परंपरा, नोटों के ढेर से ढंक गया भजन गायक

## बोरे में भरकर लाए गए थे, पूरा पैसा दान होगा

**जूनागढ़ (एजेंसी)।** गुजरात के जूनागढ़ जिले के खंभालिया गांव में श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। इसी दौरान हुए लोक डायरो (भजन कार्यक्रम) में लोक गायक जिग्नेश कविराज के ऊपर जमकर नोट बरसे। भजन कार्यक्रम अहीर समाज और प्रयागराज समूह द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान भक्तों ने गायक पर करीब डेढ़ घंटे तक रूपयों को बरसात की। कुछ लोग बोरियों में नोट भरकर लाए थे। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

**कन्या स्कूल के लिए दी जाएगी दान राशि–** अहीर समाज के आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 7 दिनों में जो भी दान राशि मिली है। वह अहमदाबाद में बन रहे 'गुजरात अहीर समाज कन्या कक्षालय' के निर्माण में दान की जाएगी। बेटियों की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए ही लोगों ने जमकर दान दिया है।

## ट्रक ने चाचा-भतीजे को 100 मीटर घसीटा, सिर-धड़ से अलग

### झांसी में बीच सड़क टुकड़ों में बिखरी लाश, दो दिन पहले ही शादी तय हुई थी

**झांसी (एजेंसी)।** झांसी में शुक्रवार को बेकाबू ट्रक ने चाचा-भतीजे को रौंद दिया। दोनों बाजार से सब्जी खरीदकर बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। भागने की कोशिश कर रहे ट्रक ने दोनों को लगभग 100 मीटर तक घसीटा। इससे चाचा के शव के कई टुकड़े हो गए और सिर भी धड़ से अलग हो गया। हादसा शुक्रवार को झांसी-कानपुर हाइवे पर चिरगांव थाना क्षेत्र में बाईपास पर हुआ है।

## दिल्ली में पहली बार दौड़ीं हाइड्रोजन बसें, इन सुविधाओं से हैं लैस

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में पहली बार हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू हो गया है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ मिलकर आज दिल्ली के सेंट्रल विस्टा एरिया में एक इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन-पावर्ड शटल बस सर्विस शुरू की है। 15 मई शुक्रवार सुबह 8:30 बजे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से पैसेंजर सर्विस के लिए दो हाइड्रोजन बसें शुरू की गईं। इन बसों की चाबियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर (रिफाइनरी), अरविंद कुमार ने डीएमआरसी और आईएसीएल के दूसरे सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में डीएमआरसी के डायरेक्टर (ऑपरेशंस एंड सर्विसेज) डॉ. अमित कुमार जैन को सौंपीं।

● मोदी के प्लेन को एफ-16 फाइटर जेट से सुरक्षा दी गई

## भारत-यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर समझौता

**दुबई (एजेंसी)।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे हैं। अबूधाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई एयरफोर्स के एफ-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम

रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू भी साइन किए गए। यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान भी किया है।

### मोदी बोले-

**होर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहना जरूरी–** मोदी ने कहा कि भारत चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित बना रहे। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है और भारत हमेशा संवाद व कूटनीति के जरिए समाधान का पक्षधर रहा है।

**यूएई पर हमले किसी भी रूप में स्वीकार नहीं–** मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे।

## भारत करवा सकता है ईरान-अमेरिका में समझौता

● नई दिल्ली में बोले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** मिडिल ईस्ट संकट और ईरान-अमेरिका टकराव के बीच रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत अपनी मजबूत कूटनीतिक छवि, संतुलित विदेश नीति और ब्रिक्स अध्यक्ष होने के नाते ईरान, अमेरिका और अरब देशों के बीच संवाद कायम कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव, तेल आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है।

● नीट अगले साल से ऑनलाइन होगी: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

## इस साल रद्द हुई परीक्षा 21 जून को

● यह पेपर-पेंसिल से होगी, सरकार ने माना- पेपर लीक हुए

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी-2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे।

उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो

जाए। इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब यह परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था। एनटीए ने सरकार को बताया। फिर 12 मई को रीएग्जाम का फैसला लिया गया।

शिक्षा मंत्री ने कहा, 'रीएग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। छात्र रीएग्जाम में अपनी पसंद का सेंटर चुन पाएंगे।' इससे पहले 3 मई को यह एग्जाम देश के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हुई था।

● नीट पेपर लीक केस में अब तक 7 गिरफ्तारियां- सीबीआई ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 यानी राजस्थान से पकड़े गए मांगी लाल बिंवाल, जमवारामगढ़ के भाई दिनेश बिंवाल, बेटा विकास बिंवाल, हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है।

## पंजाब के किसानों का चंडीगढ़ कूच, पुलिस से भिड़े

● ट्रैक्टरों से बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें छोड़ी

**चंडीगढ़ (एजेंसी)।** पंजाब के किसानों ने 15 मई को चंडीगढ़ कूच किया। किसान विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिलने जा रहे थे। इसके लिए बड़ी संख्या में किसान मोहाली के बायपीएस चौक पर जुटे, जहां से उनका चंडीगढ़ की ओर बढ़ने का कार्यक्रम था। किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट पर रही। पुलिस ने बायपीएस चौक से चंडीगढ़ जाने वाले मुख्य रास्ते को सील कर दिया। इसके अलावा सेक्टर-50 की ओर जाने वाली सड़क पर भी भारी बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि यह रास्ता राज्यपाल के आसपास के इलाके की तरफ जाता है। इसके बावजूद किसान आगे सेक्टर-50 वाले मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे।

# मप्र में 10 से 16 जून के बीच पहुंचेगा मानसून

## कटनी में ओले, उमरिया में बारिश से भीगा गेहूं, 11 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

**भोपाल (नप्र)।** मध्यप्रदेश में मानसून 10 से 16 जून के बीच दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, इस बार मानसून केरल में 26 मई के आसपास पहुंचने की संभावना है। इसके बाद यह आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश में प्रवेश करेगा। अनुमान है कि मानसून प्रदेश के पश्चिमी हिस्से- खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर के रास्ते एंट्री ले सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, इस बार प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। औसतन 30 से 32 इंच बारिश हो सकती है। भोपाल, विदिशा और सीहोर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है, जबकि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में सामान्य या उससे कम बारिश हो सकती है।

### कई जिलों में बारिश, गेहूं भीगा

इधर, मानसून की आहट के बीच प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। शुक्रवार शाम कटनी में तेज आंधी के साथ ओले गिरे। उमरिया में बारिश से खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं भीग गया। डिंडौरी के मेहदवानी और शहपुरा क्षेत्र में भी तेज आंधी-बारिश हुई, जिससे तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।

## प्रदेश में हीट वेव 'लू', 40 जिलों में गर्म हवा के थपेड़ों ने किया बेहाल, 4 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट

इन दिनों पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों को छोड़कर पूरा मध्य प्रदेश हीट वेव यानी लू की चपेट में है। मौसम केंद्र, भोपाल ने अगले 4 दिन तक प्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को करीब 40 जिलों में गर्म हवा चली। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में 15, 16 और 17 मई को तीव्र लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे ने कहा कि दोपहर 12 से 3 बजे तक गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। ऐसे में लोग जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर बना है। शाजापुर और छतरपुर के नौगांव में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों शहर प्रदेश में सबसे गर्म रहे। वहीं, 9 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा। शाजापुर-नौगांव के बाद खरगोन में पारा 44.6 डिग्री, खंडवा-रतलाम में 44.5 डिग्री, खजुराहो में 44.3 डिग्री, रायसेन-दमोह में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो उज्जैन में सबसे ज्यादा 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भोपाल में 43.4 डिग्री, जबलपुर में 43.3 डिग्री, इंदौर में 43 डिग्री और ग्वालियर में 41.8 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर रहा।

## पूरी फैक्ट्री बनते ही शुरू हुआ पटाखा निर्माण

### श्रम विभाग की रिपोर्ट में देवास हादसे की दो वजह, पानी के संपर्क में आया मैग्नीशियम

**भोपाल (नप्र)।** मध्य प्रदेश के देवास में हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में श्रम विभाग की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस हादसे को लेकर श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी तौर पर दुर्घटना की मुख्य वजह मैग्नीशियम पाउडर की केमिकल रिएक्शन हो सकती है।

**दो कारणों से हादसे की आशंका**

आशंका जताई जा रही है कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान मैग्नीशियम पाउडर का पानी से संपर्क हो गया, जिससे यह जोरदार धमाका हुआ। इसके अलावा, एक थ्योरी यह भी है कि इस बारूद की हैंडलिंग के दौरान स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया, जिसने 'सेल्फ इग्निशन' (स्वत: आग पकड़ने) का काम किया। फिलहाल मौके से सबूत जुटाकर बयानों के आधार पर विस्तृत जांच की जा रही है।

**फैक्ट्री का निर्माण पूरा नहीं हुआ, फिर भी बने पटाखे**

श्रम विभाग की इस शुरुआती रिपोर्ट ने प्रबंधन की उन गंभीर लापरवाहियों को भी उजागर कर दिया है, जो इस हादसे की नींव बनीं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह कारखाना अभी पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुआ था। निर्माणाधीन कारखाने में ही बेहद जल्दबाजी दिखाते हुए पटाखों का विनिर्माण काम शुरू कर दिया गया था। यानी जब बुनियादी सुरक्षा ढांचे की टेस्टिंग होनी चाहिए थी, तब वहां धड़ल्ले से बारूद का खेल चल रहा था।

## आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

- 50 प्रतिशत आरक्षण विवाद पर राज्य सरकार से जवाब तलब, पांच साल नौकरी के बाद भी नहीं मिला लाभ

**जबलपुर (नप्र)।** मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने आयुष चिकित्सा अधिकारियों (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी) की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने यह आदेश तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को पारित किया। खंडपीठ ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय मांगा है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 23 जून 2026 को होगी।

**पांच साल की सेवा पूरी करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं-** अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए 31 दिसंबर 2025 को जारी तीनों विज्ञापनों के तहत आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती से जुड़ी सभी आगामी कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यानी फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी।

## भोपाल में पेट्रोल का रेट 109.71, इंदौर में 109.86 रुपए प्रति लीटर

**लोग बोले- रहम करो**

**भोपाल (नप्र)।** देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। अब इसका असर मध्यप्रदेश में भी साफ दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल का दाम 106.68 रुपए से बढ़कर 109.71 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 91.87 रुपए से बढ़कर 94.88 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इंदौर में 109.86 रुपए।

इसी तरह उज्जैन में पेट्रोल 110.16 रुपए और डीजल 95.34 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। जबलपुर में पेट्रोल 110.10 रुपए और डीजल 95.28 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं, ग्वालियर में पेट्रोल 110.02 रुपए और डीजल 95.19 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोल-डीजल के बढ़े हुए दामों से आम जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ती है। कई लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब गाड़ी सोच-समझकर चलानी होगी, क्योंकि लगातार बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है।लोगों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं।

## रिटायर्ड जज और वकील बेटे पर एफआईआर

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल के ट्विशा सुसाइड मामले में उनकी सास रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसीपी रजनीश कश्यप कौल ने बताया कि मां-बेटे के खिलाफ हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित अन्य धाराओं में केस बनाया गया है। पुलिस की दो टीमें आरोपियों के घर सहित अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। दरअसल, 12 मई की रात कटारा हिल्स इलाके में 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

## प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा का सुसाइड

**घर में अकेली थी**

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने शुक्रवार सुबह फांसी लगा लगी। घटना कजलीखेड़ा इलाके की है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।

पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रेम प्रसंग सहित अन्य एंगल पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

**चार बहनों में सबसे बड़ी थी प्रियंका-** कजलीखेड़ा निवासी प्रियंका धोरे पिता घनश्याम धोरे (25) चार बहनों में सबसे बड़ी थी। घटना के समय वह घर में अकेली थी। पुलिस को उसके कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

## मध्यप्रदेश पुलिस की नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

### विगत 05 दिनों में प्रदेशभर में लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक के मादक पदार्थ जब्त

**भोपाल (नप्र)।** मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी कार्यवाही के दौरान विभिन्न जिलों की पुलिस टीमों ने विगत 5 दिनों में 1 करोड़ 43 लाख रूपए से अधिक के मादक पदार्थ, तस्करी में प्रयुक्त वाहन, मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

**शहडोल-** पुलिस द्वारा अवैध गांजा तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए लगभग 04 क्विंटल अवैध गांजा, 03 चारपहिया वाहन एवं 07 मोबाइल फोन सहित 75 लाख रूपए की संपत्ति जब्त कर 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

**मंदसौर-** जिले में पुलिस द्वारा अलग-अलग कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त की है। थाना नाहरगढ़ पुलिस ने एक कार से 01 किलो अवैध एमडी ड्रग्स जब्त कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्यवाही में लगभग 30 लाख रुपये की संपत्ति जप्?त की गई। वहीं थाना अफजलपुर पुलिस ने अवैध डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को वाहन सहित गिरफ्तार कर लगभग 8 लाख 24 हजार रुपये की संपत्ति जप्त की है। दोनों कार्यवाहियों में लगभग 38 लाख 24 हजार रुपये से अधिक की संपत्ति जप्त की है।

**रतलाम-** जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए थाना रिंगनोद पुलिस ने एमडी ड्रग्स सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर 5 लाख 50 हजार रूपए की संपत्ति जब्?त की है।वहीं थाना बरखेड़ा पुलिस ने 735 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक आरोपी एवं एक विधि विरूद्ध बालक को पकड़ा। दोनों कार्यवाहियों में पुलिस ने लगभग 7 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति जप्त की है।

**राजगढ़-** जिले में 'ऑपरेशन शुद्धि' के तहत कार्यवाही करते हुए थाना छापीहेड़ा पुलिस ने स्मैक एवं एक्टिवा स्कूटी सहित 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 लाख 20 हजार रूपए की संपत्ति जब्त की है।वहीं बोडा थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40.30 ग्राम अवैध स्मैक (5 लाख रूपए) जब्त किया।

**गुना-** जिले के मृगवास थाना पुलिस ने राजस्थान से स्मैक तस्करी कर रहे अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से स्मैक एवं तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित लगभग 06 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।

**भोपाल-** थाना हनुमानगंज पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 37 ग्राम एमडी ड्रग्स (लगभग 04 लाख रुपये) जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

**रीवा-** रीवा के थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए 608 शीशी कोडीन युक्त नशीली कफ सिरप जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जप्त कफ सिरप की अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 22 हजार रुपये है।

## मोहन कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें

**खराब प्रदर्शन वाले मंत्री टीम से होंगे आउट, बड़े चेहरों पर भी खतरा!**

**भोपाल (नप्र)।** जून माह के पहले पखवाड़े में मोहन सरकार के ढाई साल पूरे हो गए। इससे पहले एमपी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें हैं। बीजेपी आलाकमान के समीक्षक 17-18 मई को भोपल में रहेंगे। कहा जा रहा है कि मंत्रियों के परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो कुछ नए चेहरे को मौका मिल सकता है।

**मानसून सत्र से पहले कैबिनेट में बदलाव के आसार-**इस रिव्यू के आधार पर जुलाई में होने वाले मानसून सत्र से पहले मोहन कैबिनेट में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान कैबिनेट में से कुछ को हटाया जा सकता है। संभावना है कि इस लिस्ट में एक-दो वरिष्ठ मंत्रियों का नाम हो सकता है। उनकी जगह पर नए चेहरों को मोहन कैबिनेट में मौका मिलेगा।

**मंत्रियों को बैठाकर आमने-सामने होगी चर्चा-** पार्टी सूत्रों के अनुसार मंत्रियों को आमने-सामने बैठाकर उनसे चर्चा की जाएगी। इस दौरान उनके जिलों के प्रभार की स्थित, विभागों में नवाचार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल को लेकर सवाल किए जाएंगे। इसके बाद समीक्षक उनके दावों की पुष्टि करेंगे। साथ ही ढाई साल के कामकाज की समीक्षा करेंगे।

**कैबिनेट में हैं चार पद खाली-** मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव को लेकर कुल 31 मंत्री हैं। अभी चार पद खाली हैं। वहीं, कैबिनेट विस्तार की अटकलें पिछले कई महीनों से है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। इसी दिन छत्तीसगढ़ में भी सीएम ने शपथ ली थी। पिछले साल अगस्त में छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार हुआ है। गुजरात में भी हुआ है। वहीं, 10 मई को यूपी में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अब बारी मध्य प्रदेश की है।

**इन लोगों को मिल सकता है मौका-** वहीं, जिन लोगों को कैबिनेट में शामिल किए जाने की आशंका है, उनमें कुछ पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। ये पिछले ढाई साल से किसी पद के इंतजार में बैठे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह फेरबदल बिल्कुल सही समय पर हो रहा है। क्योंकि नए मंत्रियों को 2028 के चुनावों से पहले काम करने के लिए पूरे दो साल का समय मिल जाएगा।

## राज्यपाल ने प्रो. शर्मा को आरजीपीवी का किया कुलगुरू नियुक्त

**भोपाल (नप्र)।** राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगुभाई पटेल ने प्रो. आलोक शर्मा को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलगुरू नियुक्त किया है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आई.आई.टी.टी.एम.) ग्वालियर के निदेशक प्रो. आलोक शर्मा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 4 वर्ष की कालावधि के लिए कुलगुरू नियुक्त किया गया है।

## मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा की पुण्य तिथि पर दी श्रद्धांजलि

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल के. एम. करिअप्पा की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रद्धेय करिअप्पा का साहस, अनुशासन और सशक्त नेतृत्व युवा पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणादायी और अविस्मरणीय रहेगा।

## एआई से अश्लील फोटो बनाया, छात्रा ने किया सुसाइड

### भोपाल में दो युवक कर रहे थे ब्लैकमेल, पिता से भी की बदसलूकी, परिजनों ने थाना घेरा

**भोपाल (नप्र)।** भोपाल के ऐशबाग इलाके में 11वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा ने गुरुवार रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि दो युवक उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और एआई से तैयार किए गए कथित अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने शुक्रवार को ऐशबाग थाने का घेराव किया।

पुलिस के अनुसार, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। ऐशबाग थाना टीआई संदीप पवार ने बताया कि परिजनों के विस्तृत बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

- **एआई से अश्लील फोटो बनाने का आरोप-** मृतक छात्रा ऐशबाग इलाके में परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता बिट्टन मार्केट में कपड़े की दुकान चलाते हैं। वह परिवार की बड़ी बेटी थी। परिजनों का आरोप है कि छोला क्षेत्र में रहने वाला एक युवक और उसका साथी छात्रा को लंबे समय से परेशान कर रहे थे।

चाचा के मुताबिक, आरोपियों ने सोशल मीडिया से छात्रा की तस्वीरें लेकर एआई की मदद से कथित अश्लील फोटो तैयार किए थे। इन्हें वायरल करने और बदनाम करने की धमकी देकर वे छात्रा पर दबाव बनाते थे। परिवार का दावा है कि आरोपियों ने छात्रा के पिता से भी बदसलूकी की थी, लेकिन बदनामी के डर से पहले पुलिस में शिकायत नहीं की गई।

- **स्कूल आते-जाते पीछा करने का आरोप-** परिजनों का कहना है कि दोनों आरोपी छात्रा पर मिलने का दबाव बनाते थे और स्कूल आते-जाते उसका पीछा करते थे। परिवार का दावा है कि छात्रा की आरोपियों से कभी सीधी मुलाकात तक नहीं हुई थी और सोशल मीडिया से तस्वीरें लेकर उन्हें एडिट किया गया।
- **बहन को बाहर भेजकर कमरे में लगाई फांसी-** परिजनों के मुताबिक, गुरुवार रात छात्रा सामान्य थी। उसने छोटी बहन को सामान लेने के बहाने बाहर भेजा। इसी दौरान उसने कमरे में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। छोटी बहन लौटकर आई तो छात्रा को फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिवार ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
- **थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन-** पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार दोपहर परिजन शव लेकर सीधे ऐशबाग थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर घेराव कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को आरोपियों के नाम और ब्लैकमेलिंग की जानकारी देने के बावजूद तत्काल कार्रवाई नहीं की गई।

संपादकीय

# केरलम् में सतीशन पर मुहर

केरलम में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद दस दिनों तक चली ऊहापोह के बाद आखिर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता वी.डी.सतीशन को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। वो राज्य के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। केरलम् में सीएम पद की दौड़ में तीन नाम थे, जिनमें अव्वल नंबर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम पद के दावेदार के.सी.वेणुगोपाल तथा तीसरे नंबर पर वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नजदीकी के चलते वेणुगोपाल सीएम बन सकते हैं, लेकिन राज्य के लोग सतीशन के पक्ष में ज्यादा थे। यही नहीं, कांग्रेसनीत यूडीएफ गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो पहले ही सतीशन के रूप में अपनी पसंद जाहिर कर दी थी। लिहाजा इसे मुस्लिम लीग के दबाव में किया गया फैसला भी माना जा सकता है। उत्तर केरल में आईयूएमएल की भूमिका अहम है, खास तौर पर वायनाड जैसी लोकसभा में और 10 से 12 विधानसभाओं में भी उनका प्रभाव है। बावजूद इसके इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि सतीशन राज्य में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और केरल की राजनीति से उनका जमीनी जुड़ाव है। अधिकांश विधायक भी उन्हीं के पक्ष में थे। पार्टी आलाकमान ने अंतिम फैसले के पहले संगठन के विभिन्न स्तरों से फीडबैक लिया और सतीशन के पक्ष में ग्रास रूट सेंटीमेंट को ज्यादा तवज्जो दी। वैसे सतीशनको कांग्रेस नेता प्रियंका और सोनिया गांधी के भी करीबी माना जाता है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कहने पर ही बनाया गया था। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो की भूमिका अहम थी। जबकि वेणुगोपाल 6 साल से केन्द्र की राजनीति में सक्रिय हैं। उनका लोकल कनेक्ट कम हो गया था। वीडी सतीशन कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जो कि 2001 में पहली बार परवूर से चुनाव जीतने के बाद इस सीट से कभी नहीं हारे। सतीशन एलएलएम तक शिक्षित हैं। उनकी अध्ययन में गहरी रूचि है। राजनीति में उन्होंने छात्र जीवन में ही केरल स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से कदम रख दिया था। और 1986-1987 के दौरान महात्मा गांधी विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही, उन्होंने कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी निभाई। बाद में हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। चुनावी राजनीति में उनका पहला कदम 1996 में पड़ा, जब उन्होंने परावूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। यह क्षेत्र तब कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था और उन्हें भाकपा के उम्मीदवार पी. राजू से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद सतीशन ने हार नहीं मानी और क्षेत्र में सक्रिय रहे। साल 2001 में उन्हें अपनी पहली बड़ी राजनीतिक सफलता मिली, जब वे परवूर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार केरल विधानसभा के लिए विधायक चुने गए और तब से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2011 से 2016 के बीच जब राज्य में यूडीएफ (यूडीएफ) की सरकार थी, तब सतीशन पार्टी के अंदर ही एक बागी आवाज के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने हरित राजनीति का समर्थन किया और अपनी ही पार्टी के नेताओं के प्रभावशाली सामुदायिक नेताओं के आगे झुकने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने हमेशा चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए योग्यता को पैमाना बनाने की वकालत की। करोड़पति नेता सतीशन के सामने आगे कई चुनौतियां हैं। उन्हें राज्य में कांग्रेस को मजबूत करना और भाजपा के बढ़ते असर को रोकना है। साथ ही केन्द्र सरकार से बेहतर तालमेल बनाते हुए केरलम् को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। सबसे पहले तो सतीशन को अपनी ही पार्टी के केसी वेणुगोपाल से निपटना होगा, क्योंकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि वेणु सतीशन को चैन से राज करने देंगे।

नजरिया

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

# व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का आधार हो बारहवीं की परीक्षा

भारत में मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं (जैसे नीट यूजी 2026) में पेपर लीक होना एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेर देता है। जब पेपर लीक होता है, तो अयोग्य छात्र पैसे के दम पर सीट हासिल कर लेते हैं। इससे उन मेहनती और योग्य छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाता है जिन्होंने वर्षों तक दिन-रात मेहनत की होती है। बार-बार परीक्षाओं का रद्द होना या धांधली की खबरें आना छात्रों में डिप्रेशन, चिंता और सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा करता है। एक औसत भारतीय परिवार अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए जीवन भर की कमाई लगा देता है। परीक्षा रद्द होने पर कोचिंग, फॉर्म और यात्रा का अतिरिक्त आर्थिक बोझ माता-पिता पर पड़ता है। यदि पेपर लीक की सुविधा से बिना योग्यता वाले लोग डॉक्टर बनेंगे, तो भविष्य में देश की स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिरेगा, जो सीधे तौर पर जन-स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

केवल मेडिकल परीक्षाओं में ही नहीं हमारे यहां अन्य व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं में भी ऐसी पेपर लीक हो जाने की घटनाएं होती रहीं हैं। इंजीनियरिंग, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार सामने आए पेपर लीक मामलों ने युवाओं में निराशा और आक्रोश पैदा किया है।

नीट 2024 के प्रश्नपत्र लीक होने और अनियमितताओं के आरोपों ने पूरे देश में विवाद खड़ा कर दिया। कई राज्यों में गिरफ्तारी हुई और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न उठे। यूजीसी नेट (GC-NET 2024) परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया क्योंकि इसके प्रश्नपत्र डार्क वेब और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने की आशंका जताई गई। Staff Selection Commission तथा रेलवे भर्ती परीक्षाओं में कई बार तकनीकी गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोप लगे। 2018 में व्यापक छात्र आंदोलन भी हुए। व्यापमं घोटाला भारत के सबसे चर्चित परीक्षा घोटालों में से एक रहा। इसमें मेडिकल प्रवेश, भर्ती परीक्षाओं और फर्जी अभ्यर्थियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस भर्ती, पटवारी परीक्षा, शिक्षक भर्ती आदि में भी कई राज्यों में प्रश्नपत्र लीक की घटनाएँ सामने आईं। इससे लाखों परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा देनी पड़ी।

दरअसल, पेपर लीक अब छोटे स्तर की घटना नहीं रह गई है। इसमें कई बार कोचिंग माफिया, साइबर अपराधी, प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी, दलाल और कुछ भ्रष्ट अधिकारी शामिल पाए जाते हैं। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के कारण हमारी परीक्षा प्रणाली कमजोर और असुरक्षित हो गई है। कई बार प्रश्नपत्रों की छपाई, परिवहन और वितरण के दौरान पर्याप्त डिजिटल एवं भौतिक सुरक्षा नहीं होने से गोपनीयता भंग हो जाती है। बेरोजगारी और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के चलते तथा सीमित नौकरियों और सीटों के कारण परीक्षा पास करने का दबाव बहुत अधिक है। कुछ अभ्यर्थी गलत रास्ता अपनाने को लालायित हो जाते हैं। सोशल

मीडिया के टेलीग्राम, व्हाट्सऐप, ब्लूटूथ डिवाइस, डार्क वेब और हैकिंग तकनीकों का उपयोग कर प्रश्नपत्र तेजी से विस्तारित होने लगते हैं। अपराधियों को पकड़ लिए जाने के बावजूद लंबी कानूनी प्रक्रिया और दोषसिद्धि दर कम होने के कारण अपराधियों में दंड का डर कम दिखाई देता है।

घटनाओं के हो जाने के बाद एक बना बनाया रवैया अपना लिया जाता है। मामलों की जांच सीबीआई याने केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी जाती है। इस जांच के परिणाम और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही इतनी देर से हो पाती है कि छात्रों की प्रवेश की उम्र ही निकल जाती है।

खबरों के अनुसार हाल ही की 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी (NEET-UG 2026) परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जांच बहुत तेज हो गई है और इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, बताया जाता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में मास्टरमाइंड्स सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें दिल्ली की एक अदालत ने 7 दिनों की CBI हिरासत में भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पेपर बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से ही लीक किया गया, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के किसी करीबी या अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका भी हो सकती है।

अब होगा यह कि आरोपियों के खिलाफ वित्तीय जांच शुरू कर दी जाएगी, संदिग्धों के संपत्तियों का पता लगाया जाएगा। सीबीआई द्वारा कई जगहों पर छापेमारी की जाएगी और आरोपियों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज, जाली स्टैम्प और हार्ड डिस्क आदि को अपने कब्जे में लिया जाएगा या यह सब अब तक किया भी जा चुका हो। समाचार है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा फिर से कराने की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यह है कि पूर्व में ऐसे मामलों में ऐसी ही कार्यवाहियां होती रही हैं फिर भी बार बार पेपर लीक की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं क्यों हो जाती है? इनका स्थाई निदान करने में सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? यद्यपि सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए विशेषज्ञ अनेक सुझाव देते रहे हैं। तकनीकी, प्रशासनिक और कानूनी सुधार के साथ माफिया की पहचान और उन पर प्रभावी लगाम सख्ती से लगाने की बातें भी खूब कही गई हैं। पूरी तरह डिजिटल परीक्षा, डिजिटल रूप से प्रश्न पत्रों कुछ मिनट पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाना जो केवल पास वर्ड की मदद से ही खुल सकें, एआई तथा बायो मीट्रिक तकनीक सत्यापन से डमी कैंडिडेट को रोका जाना साथ ही पकड़े जाने पर 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपयों के जुर्माने के सुझाव और नियम कानूनों के उपरांत भी घटनाओं का होना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। संदेह जताया जाता है कि अक्सर पेपर लीक के तार बड़े कोचिंग संस्थानों या संगठित अपराधियों से जुड़े होते हैं। यह सोचा जाना चाहिए कि सरकार द्वारा कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त पंजीकरण और निगरानी प्रणाली विकसित करने में देरी क्यों हो जाती है।

मेडिकल और कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए दुनिया भर मेंप्रवेश की प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं। कई देशों में कठिन प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो केवल स्कूल के अंकों (12वीं या हायर सेकेंडरी) के आधार पर प्रवेश देते हैं।जिन देशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग से कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती (या अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रक्रिया सरल है)। यहाँ मुख्य रूप से 12 वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अंकों के आधार पर प्रवेश मिल जाता है उनमें रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रोमानिया, जॉर्जिया देश शामिल हैं। क्या हम व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं की बजाए इसी तरह हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं? ऐसा होने से हमारी स्कूली शिक्षा का स्तर भी उल्लेखनीय रूप से गुणवत्तापूर्ण हो सकेगा।

बच्चों का भविष्य बचाने के लिए केवल तकनीक काफी नहीं है, बल्कि एक 'नैतिक संस्कृति' विकसित करने की जरूरत है। जब तक परीक्षा कराने वाली एजेंसियां, प्रिंटिंग प्रेस और केंद्र अधीक्षक पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण सुरक्षा कठिन है। पेपर लीक केवल परीक्षा से जुड़ी तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह युवाओं के विश्वास, सामाजिक न्याय और राष्ट्र की प्रतिभा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। यदि योग्य और मेहनती विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा, तो देश की शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होगी। इसलिए सरकार, परीक्षा एजेंसियों, तकनीकी विशेषज्ञों और समाज को मिलकर ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जिसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

# सेप्सिस का अदृश्य खतरा और हमारी स्वास्थ्य रणनीति

स्वास्थ्य

कुमार सिद्धार्थ एवं डॉ. सम्यक जैन

हमारे देश के मौजूदा स्वास्थ्य परिदृश्य में, जहां डेंगू, मलेरिया, टीबी, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियां पहले से ही भारी दबाव पड़ रही हैं, सेप्सिस एक ऐसा खतरा बनकर उभर रहा है जो अक्सर नज़र नहीं आता, लेकिन सबसे घातक साबित होता है। देश के अस्पतालों में सेप्सिस अब एक रोज़मर्रा की हकीकत बन चुका है। गहन चिकित्सा कक्ष (ICU) में भर्ती हर चौथा मरीज़ किसी न किसी संक्रमण से उपजी सेप्सिस जैसी गंभीर स्थिति में पाया जाता है। नवजात मृत्यु के कारणों की पड़ताल करें तो लगभग एक-तिहाई मौतें सीधे सेप्सिस से जुड़ी मिलती हैं।

ग्रामीण भारत में यह स्थिति और भी घातक रूप ले लेती है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं और संक्रमण की पहचान अक्सर देर से होती है। कई बार समय पर एंटीबायोटिक या सही हस्तक्षेप न मिलने पर मरीज़ कुछ ही घंटों में मौत के करीब पहुंच जाता है।

दरअसल, सेप्सिस को केवल संक्रमण की जटिलता मानना भ्रामक है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अनियंत्रित होकर अपने ही अंगों पर हमला करने लगती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है और संक्रमण से पैदा हुई सूजन पूरे शरीर में फैलकर दिल, फेफड़ों, गुर्दों और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा देती है। सरल शब्दों में, सेप्सिस संक्रमण के कारण शरीर का अपने ही खिलाफ सिर उठाना है। और, यही इसे इतना घातक और उग्र बना देता है।

हमारे देश में सेप्सिस की भयावहता इस बात से भी साफ होती है कि अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज़ों के लिए मृत्यु का बड़ा कारण अब यही बनता जा रहा है। नवजात शिशुओं में यह स्थिति कई बार जन्म के तुरंत बाद होने वाले संक्रमणों से उभरती है। प्रसूता-गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

हमारे देश में सेप्सिस एक छिपी महामारी की तरह व्यवहार करता है। अन्य बीमारियों की अंतिम और सबसे घातक कड़ी अक्सर यही बनता है। इसलिए सेप्सिस को अब एक अलग स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में देखने और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए विशेष रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है।

आंकड़े बताते है कि दुनिया भर में सेप्सिस हर साल एक करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान लेता है, जो वैश्विक मौतों का पांचवां हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ के अध्ययन बताते हैं कि सेप्सिस की सर्वाधिक मार निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर पड़ती है, जिनमें भारत भी शामिल है। अपने देश में वर्ष 2017 के अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ 13 लाख मामले और करीब 29 लाख मौतें इसी के कारण हुई हैं। आईसीयू आधारित शोध बताते हैं कि देश के गहन चिकित्सा कक्षों में हर दो में से एक मरीज़ किसी न किसी रूप में सेप्सिस से पीड़ित पाया जाता है, और ऐसे मरीज़ों की अस्पताल मृत्यु दर 30-40 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। नवजात शिशुओं में यह बोझ और भी भारी है, जहां करीब एक-तिहाई मौतें संक्रमणजन्य सेप्सिस से जुड़ी पाई गई हैं।

लेकिन इस गंभीर बीमारी पर हो रहे शोध की स्थिति निराशाजनक है। दुनिया और भारत में, सेप्सिस पर होने वाला अधिकांश वैज्ञानिक कार्य अभी भी उस पुराने ढांचे पर टिका है, जिसमें चूहों, खरगोशों, गिनी पिगों, बकरियों, कुत्तों और कभी-कभी बंदरों तक पर प्रयोग किए जाते हैं। इन जानवरों को प्रयोगशाला की परिस्थितियों में जबरन संक्रमित किया जाता है, आंतों में छेद करके बैक्टीरिया फैलाया जाता है या उन्हें बैक्टीरियल ज़हर की उच्च खुराक दी जाती है। लेकिन मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया इन जानवरों से इतनी अलग है कि ऐसे प्रयोगों से मिलने वाले परिणाम मनुष्यों पर लगभग कभी लागू नहीं होते।

पिछले चार दशकों में डेढ़ सौ से अधिक ऐसी दवाएं रही हैं, जो चूहों या अन्य जंतुओं में सेप्सिस का इलाज करती दिखीं, पर मानव परीक्षण में पूरी तरह असफल रहीं। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों, जैसे - स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एनआईएच आदि का निष्कर्ष है कि जंतु-आधारित मॉडल सेप्सिस का मानव स्वरूप समझने के लिए विश्वसनीय साधन नहीं हैं।

अपने देश में भी स्थिति अलग नहीं है। आईसीएमआर के कई प्रतिष्ठित केंद्र, कुछ ऐम्स संस्थान और निजी बायोमेडिकल प्रयोगशालाएं आज भी जंतु-आधारित मॉडल को सेप्सिस अध्ययन का आधार बनाए हुए हैं। इन परीक्षणों की पारदर्शिता कम है और उनसे मिलने वाले वैज्ञानिक परिणाम अत्यंत सीमित। जिस बीमारी के कारण अस्पतालों में लाखों मरीज़ चुपचाप मौत के करीब पहुंच रहे हों, उसके शोध का तरीका अगर मानव-प्रासंगिक न हो तो समाधान हमेशा दूर ही बना रहेगा।

अलबत्ता, तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। भारत में कुछ वैज्ञानिक संस्थान नई दिशाएं भी टटोल रहे हैं। आईआईटी मद्रास का ऑर्गन्स-ऑन-चिप्स कार्यक्रम, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) का सेप्सिस प्रेडिक्शन मॉडल, ऐम्?स दिल्ली में नवजात सेप्सिस के लिए विकसित बायोमार्कर और कुछ निजी प्रयोगशालाओं में एआई आधारित सेप्सिस अलर्ट सिस्टम ये सब संकेत देते हैं कि भारत आधुनिक, मानव-आधारित विज्ञान अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दुनिया भर में अब एआई-आधारित निदान और कम्प्यूटेशनल सिमुलेशन को भविष्य की दिशा माना जा रहा है। ये पद्धतियां न केवल अधिक विश्वसनीय हैं, बल्कि जानवरों पर होने वाली क्रूरता और वैज्ञानिक विफलताओं से भी मुक्त हैं।

भारत में सेप्सिस की भयावहता जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से हमें विज्ञान की दिशा बदलने की ज़रूरत है। आधुनिक तकनीकें हमारे सामने उपलब्ध हैं। ज़रूरत सिर्फ यह है कि हम पुरानी, अप्रासंगिक और अमानवीय शोध पद्धतियों को पीछे छोड़कर वैज्ञानिक रूप से अधिक सटीक, मानवीय और प्रभावी मॉडल अपनाएं। सेप्सिस के खिलाफ यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हम विज्ञान और संवेदना दोनों के सही मिश्रण के साथ आगे बढ़े। भारत को स्वास्थ्य विज्ञान के इस नए युग में कदम रखने की आवश्यकता है। यह परिवर्तन न सिर्फ लाखों लोगों की जान बचा सकता है बल्कि अनगिनत जानवरों को अनावश्यक और पीड़ादायक प्रयोगों से भी मुक्त कर सकता है।

# कोरट-कचहरियों की सम्मानजनक विदाई का स्वर्णिम दिन

कटाक्ष

शांतिलाल जैन

लेखक स्तंभकार हैं।

सूरज आज पूरब से तो नहीं ही निकला होगा। लोकतंत्र की स्थापना के आठ दशक से भी कम में मुल्क का भ्रष्टाचारियों, अपराधियों से मुक्त हो जाना कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। ऐसी कामयाबी उसी दिन मिला करती है जिस दिन सूरज पूरब से ना निकला हो। मुझे पक्का यकीन है आज सूरज पूरब से तो नहीं ही निकला होगा।

आज हुआ ये श्रीमान् कि इसके पहले कि आला कचहरी में वकील सा। अपने मुवक्किल के निर्दोष होने की अपील-दलील पेश कर पाते, जिरह होती, गवाहों सबूतों की बिला पर अपने मुवक्किल को दोषमुक्त करा पाते ड्रू प्रॉसिक्यूशन ने केस ही वापस ले लिया!!! अभियुक्त पिछली रात नौ बजे तक अपोजिशन में था, अगली सुबह नौ बजे हाकिम के दल में शामिल हो गया। सुबह का भूला था श्रीमान, अगले दिन सुबह घर आ गया था, सो आप उसे भूला नहीं कह सकते। कभी मिला करती थी क्लीन चिटें अदालतों से, अब हाकिम ने मुकदमा वापिस लेकर उसकी जरूरत ही खतम कर दी है। रख लें अदालतें अपनी चिटें अपने पास।

हाकिम ने पार्टी का बड़ा और भव्य दफ्तर बनवाया है मगर बाहर डोर-बेल नहीं लगवाई। दरवज्जे पे न्याय का घंटा जो लटकवा लिया है। बजाईए। अंदर जाईए। क्लीन चिट पाईए और पाईए एक मलाईदार ओहदा भी। स्मार्ट लीडर्स करप्शन करके कारागार का रुख नहीं करते, उनके गेट पर लटका न्याय का घंटा बजा लेते हैं और सेफ झोन में प्रवेश कर जाते हैं। 'सत्तापक्ष में कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता और विपक्ष में कोई ईमानदार नहीं होता।' न्यायशास्त्र का ये नया सिद्धांत है, जो इस अवधारणा को स्थापित करता है कि एक विपक्षमुक्त मुल्क ही भ्रष्टाचार मुक्त मुल्क का पर्याय होता है। देखते देखते न विपक्ष में न कोई नेता बचा है न मुल्क में भ्रष्टाचार का कोई आरोपी। इस तरह आज का मुकदमा दीवानी अदालतों में आखिरी मुकदमा साबित हुआ।

क्रिमिनल केसेस पहले ही अदालतों में पेश होना बंद हो चुके थे। इसे आप कल्लू मिर्ची के केस से समझिए। उसकी बदमाशी का मुआमला सामने आया और हाकिम के नुमाईंदे जेसीबी पर सवार होकर निकल पड़े। देखते देखते उसका मकान ध्वस्त कर दिया गया। लो साहब, हो गया न्याय। धरा रह गया सत्र न्यायालय और बैठे रह गये 'युवर ऑनर'। पड़ीं रह गई एफआईआर, तफ़्तीश, साक्ष्य, विवेचना, केसडायरी, रिमांड, जमानत, चार्जशीट, भारतीय न्याय संहिता, वकील, मुवक्किल। कोर्ट-कचहरी के चक्कर में अब ना हाकिम पड़ता है न उसके नुमाईंदे। उनकी मर्ज़ी ही 'ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ' है। मुल्क के आईन में अब अदालतों की जरूरत ही नहीं बची। पूरी न्यायपालिका एक झटके में बेरोज़गार हो गई है। वकीलों, न्यायाधीशों, कचहरी के कारकूनों का रोज़गार छिन गया हैं। जस्टिस सर की बेंच पर नया कोई केस लिस्ट हो नहीं रहा। कारकून खाली बैठे हैं। वकील मुवक्किलों की तलाश में भटक रहे हैं। 'हाजिर हो' की आवाजें गुम हैं, निस्तब्ध निरापद सन्नाटा पसरा पड़ा है। आज का दिन न्यायपालिका की सम्मानजनक विदाई का दिन है।

लोकतंत्र की स्थापना के आठ दशक से भी कम में ही न्यायपालिका की जरूरत का खत्म हो जाना कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। ऐसी कामयाबी उसी दिन मिला करती है जिस दिन सूरज पूरब से ना निकला हो। मुझे पक्का यकीन है आज सूरज पूरब से तो नहीं ही निकला होगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

**प्रधान संपादक**
उमेश त्रिवेदी
**कार्यकारी प्रधान संपादक**
अजय बोकिल
**संपादक (मध्यप्रदेश)**
विनोद तिवारी
**वरिष्ठ संपादक**
पंकज शुक्ला
**प्रबंध संपादक**
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

निर्मल गुप्त

लेखक व्यंग्यकार हैं।

# नीट, लीक और मंशा पर सवाल

**सज्जन जी यह सुन इस तरह मन ही मन हँसे जैसे कोई तपस्वी ज्ञान की जरा-सा आहट पा विहँसे। रूहानियत में आकंठ डूबा आदमी नीट के जरिये ही जीते जी निर्वाण को प्राप्त होता बताया जाता है। फिर उन्हें भान हुआ नीट तक तो ठीक लेकिन यह लीक क्या बला है? मोबाइल पर आने वाली खबरें थोड़ा कसैली तो होती हैं,कभी-कभी अफवाह भी पाई जाती हैं लेकिन ऐसी नहीं होती जिन्हें 'चनडूखाने' वाली बतकही' समझ लिया जाए।**

यह उस समय की बात है जब बातों ही बातों में पेपर लीक हो जाया करते थे। एक पेपर लीक होने की अपुष्ट खबर जब एक सज्जन जी के मोबाइल तक जा पहुंची तो वह चिहुंक के बोल उठे - लो जी नीट फिर लीक हो गया। उस वक्र वह मद्धम रौशनी वाले एक पब में बैठे हौले -हौले बजते रूहानी संगीत की संगति में अपने एक सरोकारी मित्र के साथ बैठे रसरंजन कर रहे थे। सज्जन जी ने जो कहा उसके सरोकारी जी महज दो लफ्ज़ सुने। नीट और लीक। वह बोल उठे - नीट तो बर्फ की डली के अधबीच सदा नीट ही रहती है, वह न छलकती है, न लीक होती है, बस सुरूर में झलकती भर है।

सज्जन जी यह सुन इस तरह मन ही मन हँसे जैसे कोई तपस्वी ज्ञान की जरा-सा आहट पा विहँसे। रूहानियत में आकंठ डूबा आदमी नीट के जरिये ही जीते जी निर्वाण को प्राप्त होता बताया जाता है। फिर उन्हें भान हुआ नीट तक तो ठीक लेकिन यह लीक क्या बला है? मोबाइल पर आने वाली खबरें थोडा कसैली तो होती हैं,कभी कभी अफवाह भी पाई जाती हैं लेकिन ऐसी नहीं होती जिन्हें 'चनडूखाने' वाली बतकही' समझ लिया जाए।

सज्जन जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने सरोकारी जी से पूछ ही लिया की ये लीक वीक है क्या बला ? सरोकारी जी ने इस जिज्ञासा को निरर्थक समझ बड़ी अदा के साथ कंधे उचकाए। लगभग कंधे इस तरह से उपर नीचे किये जैसे अमूमन अंग्रेजीदां लोग किसी भी किस्म की बहस से खुद को बचा ले जाने के लिए करते हैं। वैसे भी कंधे उचकाना टाइप का जेस्चर बॉडी लैंग्वेज के व्याकरण के हिसाब से बहुआयामी होती है। अकसर कंधे उचकाता आदमी कमोबेश बड़ा पढ़ा -लिखा सा जेंटलमैन लगता है।

सज्जन जी ने नीट द्रव का बड़ा- सा घूँट भरा और सोचा कि यदि सब कह रहे हैं तो कुछ न कुछ लीक हुआ ही होगा। फिर उन्होंने खुद से प्रतिप्रश्न किया कि आज कोई हमारा वाला टाइम थोड़े हैं कि कमीज में ऊपर लगी जेब में टांगा फोंटेन पैन खुद भी खुद लीक हो कर अच्छी भली शर्ट को डिजाइनर श्रेणी की पोषाक बना दे। वे दिन बड़े भले भले से थे जब परीक्षा शुरू होने से पूर्व लीक हुई स्याही को शुभ शगुन मान लिया जाता था । उन दिनों घर से काम पर जाते हुए कामकाजी गोलाकार टिफिन लेकर उसे झुलाते हुए चलते थे और अफसर टाइप के लोग आयताकार चपटे डिब्बे अपना लंच ब्रीफकेस में रख कर। उन दिनों शायद ही कोई बचा हो जिसके सरकारी कागज या पतलून टिफिन या लंचबॉक्स में रखे अचार के तेल के रिसाव से दागदार न हुए हो।

लेकिन ये नीट का रिसाव या लीक हो जाना तो अद्भुत है। बतातें हैं 'लीकर' इतने निष्णात थे कि बनते ड्रू बनते ही पेपर ले उड़े। इस साइबर काल में गोपनीयता एक निरर्थक शब्द है। इस एआई के जमाने में तो मन की किसी गहरी सतह पर टिकी मंशा तक आननफानन में यदि कभी वायरल हो जाये तो कोई आश्चर्य नहीं। तमाम एआई टूल आपको आपसे अधिक जानते हैं। वे निर्मल और निर्मल में कोई भेद अकसर नहीं करते एक निर्मल के बायो में विविध निर्मलों और समान नामधारी बाबाओं का समावेश कर देते हैं।

सज्जन जी अब समझ गये हैं की कोई नीट कितना भी नीट क्लीन होने का दावा करे पर सेफ नहीं है। इसके बरअक्स सरोकारी जी का कहना है कि सत्ता के ऊपरी सिरे पर कोई भारी गड़बड़ है, जो रह रह कर यहाँ वहां लीकेज होती ही रहती है। वह बिना कंधे उचकाये एलानिया कह रहे हैं कि यदि इसकी सघन जांच हो तो हो न हो इस लीकेज की जड़ें जलडमरू मध्य (जिसे लोग आजकल होर्मुज कहते हैं) में मिलेगी।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस

जयदेव राठी

लेखक अधिवक्ता हैं।

# जागरूकता से आगे बढ़कर स्थायी समाधान की जरूरत

**विश्व स्तर पर देखा जाए तो डेंगू तेजी से फैलती बीमारियों में शामिल हो चुका है। पहले जिन क्षेत्रों में यह बीमारी नहीं थी, अब वहाँ भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तापमान बढ़ने और मौसम के बदलते पैटर्न ने मच्छरों के जीवन चक्र को प्रभावित किया है। लंबे समय तक गर्मी और नमी बने रहने से मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी बड़ा खतरा बन चुका है। भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। देश के लगभग सभी राज्यों में डेंगू के मामले सामने आते हैं। महानगरों से लेकर छोटे शहर और गाँव तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हर वर्ष स्थिति गंभीर हो जाती है। सरकारी आँकड़े कई बार वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाते क्योंकि बड़ी संख्या में लोग निजी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं या जाँच तक नहीं करवा पाते।**

हर वर्ष भारत में 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि उस बढ़ते स्वास्थ्य संकट की याद दिलाने वाला दिन है जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। कभी केवल बरसात के मौसम तक सीमित रहने वाला डेंगू अब पूरे वर्ष चुनौती बनता जा रहा है। बदलती जलवायु, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमजोरियाँ इस बीमारी को और खतरनाक बना रही हैं। डेंगू आज केवल एक बीमारी नहीं बल्कि विकास, पर्यावरण और प्रशासन से जुड़ा बड़ा प्रश्न बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले दो दशकों में डेंगू के मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है और अब यह 100 से अधिक देशों में फैल चुका है। एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका इसके सबसे बड़े केंद्र बन चुके हैं। भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। हर वर्ष लाखों लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं और हजारों परिवार आर्थिक व मानसिक संकट झेलते हैं।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और नई स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि डेंगू को केवल मौसमी बीमारी मानने की गलती न की जाए बल्कि इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़कर देखा जाए।

डेंगू मच्छर जनित बीमारी है जो मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण फैलती है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है और दिन के समय काटता है। यही कारण है कि शहरों में घरों की छतों पर रखी टंकियाँ, कूलर, गमले, पुराने टायर और खुले बर्तन इसके सबसे बड़े प्रजनन केंद्र बन जाते हैं। विडंबना यह है कि आधुनिक जीवनशैली और सुविधाएँ ही कई बार बीमारी का कारण बन रही हैं।

विश्व स्तर पर देखा जाए तो डेंगू तेजी से फैलती बीमारियों में शामिल हो चुका है। पहले जिन क्षेत्रों में यह बीमारी नहीं थी, अब वहाँ भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तापमान बढ़ने और मौसम के बदलते पैटर्न ने मच्छरों के जीवन चक्र को प्रभावित किया है। लंबे समय तक गर्मी और नमी बने रहने से मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी बड़ा खतरा बन चुका है। भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। देश के लगभग सभी राज्यों में डेंगू के मामले सामने आते हैं। महानगरों से लेकर छोटे शहर और गाँव तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हर वर्ष स्थिति गंभीर हो जाती है। सरकारी आँकड़े कई बार वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाते क्योंकि बड़ी संख्या में लोग निजी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं या जाँच तक नहीं करवा पाते।

भारत की सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या घनत्व और अव्यवस्थित शहरीकरण है। तेजी से फैलते शहरों में जल निकासी की खराब व्यवस्था, गंदगी और निर्माण स्थलों पर जमा पानी डेंगू के लिए आदर्श परिस्थितियाँ तैयार करते हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और सीमित स्वास्थ्य सुविधाएँ समस्या को और बढ़ा देती हैं।

हालाँकि भारत ने डेंगू नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास भी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। स्कूलों, पंचायतों और शहरी निकायों को इसके नियंत्रण में जोड़ा जा रहा है। कई राज्यों ने विशेष फॉगिंग अभियान, साफ-सफाई अभियान और अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए हैं। भारत में वैज्ञानिक स्तर पर भी डेंगू को लेकर शोध बढ़ा है और वैक्सीन व नई उपचार तकनीकों पर कार्य हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था ने यह सीखा कि केवल अस्पताल बढ़ा देने से स्वास्थ्य संकटों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। रोकथाम सबसे प्रभावी उपाय है। डेंगू के मामले में भी यही सत्य है। यदि लोग अपने घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने दें तो बड़ी संख्या में मामलों को रोका जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जागरूकता अक्सर केवल पोस्टर और नारों तक सीमित रह जाती है।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा समाज स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रहा है? कई लोग आज भी यह मानते हैं कि सफाई केवल सरकार का काम है जबकि वास्तविकता यह है कि डेंगू नियंत्रण में नागरिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी लापरवाही पूरे मोहल्ले के लिए खतरा बन सकती है।

इसके साथ ही सरकारों को भी आत्ममंथन करना होगा। हर वर्ष बरसात से पहले डेंगू नियंत्रण की योजनाएँ बनती हैं लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में काम बहुत धीमा है। शहरों की जल निकासी व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, अवैध निर्माण और सार्वजनिक सफाई की समस्याएँ वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। स्वास्थ्य बजट बढ़ाने और स्थानीय निकायों को मजबूत करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

दुनिया के कई देशों ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से डेंगू नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है। सिंगापुर इसका बड़ा उदाहरण है जहाँ कठोर नियमों और जनजागरूकता के कारण डेंगू पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया। भारत जैसे विशाल देश में यह चुनौती कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। आवश्यकता केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक योजना और सामाजिक भागीदारी की है। डेंगू का आर्थिक प्रभाव भी कम नहीं है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इलाज का खर्च भारी बोझ बन जाता है। निजी अस्पतालों में प्लेटलेट्स और उपचार के नाम पर भारी बिल वसूले जाते हैं। कई बार डर और अफवाहें भी लोगों की परेशानी बढ़ा देती हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और सस्ती चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जरूरी है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस केवल बीमारी की चर्चा करने का अवसर नहीं होना चाहिए बल्कि यह आत्मविश्लेषण का दिन बनना चाहिए। क्या हमारे शहर रहने योग्य बन रहे हैं? क्या विकास योजनाओं में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जब तक इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार नहीं होगा तब तक हर वर्ष डेंगू नए रूप में सामने आता रहेगा। भारत के पास दुनिया को दिशा देने का अवसर भी है। जिस तरह भारत ने वैक्सीन निर्माण, दवाइयों और जनस्वास्थ्य अभियानों में वैश्विक पहचान बनाई है उसी प्रकार डेंगू नियंत्रण में भी वह नेतृत्व कर सकता है। इसके लिए शोध, तकनीक, स्वच्छता और जनभागीदारी को एक साथ जोड़ना होगा।

आज आवश्यकता केवल एक दिवस मनाने की नहीं बल्कि एक स्थायी जनआंदोलन खड़ा करने की है। यदि हर नागरिक सप्ताह में केवल दस मिनट अपने घर और आसपास जमा पानी की जाँच कर ले तो डेंगू के खिलाफ बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस का वास्तविक उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि बीमारी के बाद इलाज नहीं, बल्कि बीमारी से पहले बचाव की संस्कृति विकसित हो। डेंगू के खिलाफ लड़ाई सरकार, समाज और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। जब तक यह जिम्मेदारी सामूहिक रूप से नहीं निभाई जाएगी तब तक हर बरसात के साथ अस्पतालों की भीड़, बढ़ती चिंताएँ और स्वास्थ्य संकट की खबरें दोहराई जाती रहेंगी। अब समय आ गया है कि जागरूकता को आदत और अभियान को संस्कृति बनाया जाए।

राजनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

# वीडी सतीशन: जमीनी योद्धा का सम्मान

**गुरुवार की सुबह सुश्री दीपा दासमुंशी के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन तथा वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की मौजूदगी में इस आशय की घोषणा से अंततः अटकलों का कुहासा छंट गया और यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी नेतृत्व अपने जमीनी योद्धा का चयन करने के मूड में है और केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला कुर्सी की दौड़ में पिछड़ गये हैं। यह ऐलान इसलिये भी मानीखेज था, क्योंकि यह खबर छनकर आ रही थी कि निर्वाचित विधायकों का बहुमत वेणुगोपाल के साथ है, जिन्हें पार्टी में दिल्ली की किल्ली के नजदीक माना जाता है। लेकिन बुधवार की शाम पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माकन, दासमुंशी और वासनिक से विमर्श ने सतीशन का नाम आगे कर दिया। इसके बाद घड़ी के कांटे तेजी से घूमे। गुरुवार की सुबह राहुल गाँधी ने केसी वेणुगोपाल से चर्चा की। तकरीबन तीस मिनट की बातचीत में राहुल अपने निकट सहयोगी को दौड़ से हटने के लिये मनाने में सफल रहे और इसके कुछ घंटों बाद विधिवत वीडी के नाम की घोषणा कर कर दी गयी।**

दासरी दामोदरन (वीडी) सतीशन अब साक्षर-राज्य केरलम के मुख्यमंत्री होंगे। दस दिनों की माथा-पच्ची और रायशुमारी के उपरांत अंततः 14 मई को दिल्ली में उनके नाम का ऐलान हो गया। गुरुवार की सुबह सुश्री दीपा दासमुंशी के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन तथा वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की मौजूदगी में इस आशय की घोषणा से अंततः अटकलों का कुहासा छंट गया और यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी नेतृत्व अपने जमीनी योद्धा का चयन करने के मूड में है और केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला कुर्सी की दौड़ में पिछड़ गये हैं। यह ऐलान इसलिये भी मानीखेज था, क्योंकि यह खबर छनकर आ रही थी कि निर्वाचित विधायकों का बहुमत वेणुगोपाल के साथ है, जिन्हें पार्टी में दिल्ली की किल्ली के नजदीक माना जाता है। लेकिन बुधवार की शाम पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माकन, दासमुंशी और वासनिक से विमर्श ने सतीशन का नाम आगे कर दिया। इसके बाद घड़ी के कांटे तेजी से घूमे। गुरुवार की सुबह राहुल गाँधी ने केसी वेणुगोपाल से चर्चा की। तकरीबन तीस मिनट की बातचीत में राहुल अपने निकट सहयोगी को दौड़ से हटने के लिये मनाने में सफल रहे और इसके कुछ घंटो बाद विधिवत वीडी के नाम की घोषणा कर कर दी गयी।

31 मई, सन् 1964 को नेत्तूर में जनमे सतीशन खाँटी कांग्रेसी नेता हैं। छात्र जीवन में वह एनएसयूआई से जुड़ गये। सन् 1986-87 में वह महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे। यूनिवर्सिटी आफ केरल से उन्होंने एलएलएम किया और हाईकोर्ट में दस साल प्रैक्टिस। सन् 1996 में उन्होंने परवूर से असेंबली का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन 'प्रथम ग्रासे मक्षिकापातः' की तर्ज पर वह सीपीआई के पी. राजू से हार गये। सन 2001 के चुनाव में उन्होंने राजू हिसाब चुकता किया और इसके बाद क्रमशः केएम दिनकरन, रवीन्द्रन, शारदा मोहन और एमटी निक्सन जैसे नेताओं को हरा कर लगातार असेंबली में पहुंचे। सन 2021 में रमेश चेन्निथला के स्थान पर नेता प्रतिपक्ष बने और तदंतर विधानसभा के भीतर और बाहर अपनी सक्रियता से सबका ध्यान आकृष्ट किया। केरलम के कांग्रेस नेताओं में वह संघर्ष, साख और सक्रियता के मामले में सबसे आगे हैं। कोट्टायम के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक निजाम सैयद के मुताबिक सतीशन इज द बेस्ट च्वॉयस फॉर चीफ मिनिस्टरशिप। जनभावनाओं का ज्वार उनके साथ है और कार्यकर्ता उनके पीछे।

आखिर क्या वजह है कि निजाम व अन्य मलयाली पत्रकार सतीशन को 'सर्वोत्तम पसंद' निरूपित कर रहे हैं वजह साफ है। सतीशन जमीनी योद्धा है और आडंबर से कोसों दूर। वह कुशल और प्रभावशाली वक्ता हैं और उन्हें सुनना 'सांद्र अनुभव' से गुजरना है। वह लेखक तो नहीं, अलबत्ता गंभीर पाठक हैं और साहित्यिक जलसों में उन्हें आग्रहपूर्वक बुलाया जाता है। आधुनिक मलयाली साहित्य में उनकी गहरी रूचि है और वह जेन-जी में बेहद लोकप्रिय है। उन्हें सियासी नजूमी भी माना जा सकता है, क्योंकि चुनावों में उनकी भविष्यवाणियाँ खरी उतरती रही हैं। इस दफा तो उन्होंने सार्वजनिक ऐलान कर कर दिया था कि यदि यूडीएफ को सौ से कम सीटें मिलीं तो वह राजनीति सन्यास ले लेंगे। केरलम में काँग्रेसनीत गठबंधन को जिताने में उन्होंने रात-दिन एक कर दिया। पार्टी में उन्हें 'टास्क मास्टर' माना जाता है और इसके चलते वह प्रियंका और राहुल के विश्वासपात्र बनकर उभरे। मासांत में वह अपना 62वीं वर्षगांठ बतौर सीएम मनायेंगे। उनका टास्क मास्टर होना यकीनन उम्मीदें जगाता है। त्रिवेंद्रम और दिल्ली में चले दस दिनी घटनाक्रम ने यह भी दर्शा दिया कि महत्वाकांक्षी शशि थरूर के नाम पर कहीं कोई विचार नहीं किया गया।

यात्रा संस्मरण

मोहन वर्मा

लेखक पत्रकार हैं।

# रोमांच, आस्था और प्रकृति का अद्भुत सफर

**देवास की 44 डिग्री तापमान वाली तपती गर्मी से निकलकर हम तीन मित्र पहुँचे हल्द्वानी। हल्द्वानी से कुछ दूरी पर स्थित काठगोदाम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड का अंतिम रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहीं से पहाड़ों का वास्तविक सफर शुरू होता है। घुमावदार सड़कें, बादलों से घिरी पहाड़ियाँ और घाटियों में बहती नदियाँ मन को रोमांच से भर देती हैं। सड़क मार्ग से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे पिथौरागढ,जो इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण बेस कैंप है। वहाँ से हमारा कारवाँ पहुँचा धारचूला, जो भारत-नेपाल सीमा पर बसा एक सुंदर कस्बा है। इसके साथ-साथ बहती काली नदी का हरा, निर्मल जल और कल-कल करता प्रवाह मन को मोह लेता है। नदी के एक ओर भारत और दूसरी ओर नेपाल की बस्तियाँ दिखाई देती हैं। यही रास्ता आगे कैलाश मानसरोवर, आदिकैलाश और ओम पर्वत तक जाता है।**

पर्यटन प्रेमी और घुमक्कड़, चाहे वे किसी भी उम्र के हों, हर जगह मिल जाते हैं। कोई प्रकृति की अनुपम सुंदरता देखने निकलता है तो कोई दुर्गम पहाड़ों में बसे आस्था के केंद्रों की ओर खिंचा चला जाता है। हिमाचल, सिक्किम, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारधाम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और अंडमान-निकोबार की यात्राओं के बाद इस बार हमारा कारवां निकला आदिकैलाश और ओम पर्वत की ओर।

देवास की 44 डिग्री तापमान वाली तपती गर्मी से निकलकर हम तीन मित्र पहुँचे हल्द्वानी। हल्द्वानी से कुछ दूरी पर स्थित काठगोदाम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड का अंतिम रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहीं से पहाड़ों का वास्तविक सफर शुरू होता है। घुमावदार सड़कें, बादलों से घिरी पहाड़ियाँ और घाटियों में बहती नदियाँ मन को रोमांच से भर देती हैं।

सड़क मार्ग से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे पिथौरागढ,जो इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण बेस कैंप है। वहाँ से हमारा कारवाँ पहुँचा धारचूला, जो भारत-नेपाल सीमा पर बसा एक सुंदर कस्बा है। इसके साथ-साथ बहती काली नदी का हरा, निर्मल जल और कल-कल करता प्रवाह मन को मोह लेता है। नदी के एक ओर भारत और दूसरी ओर नेपाल की बस्तियाँ दिखाई देती हैं। यही रास्ता आगे कैलाश मानसरोवर, आदिकैलाश और ओम पर्वत तक जाता है।

रास्ते में सबसे पहले हमने दर्शन किए नीम करौली बाबा के आश्रम के। देशभर से श्रद्धालु यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। पहाड़ों की शांत वादियों में स्थित यह धाम मन को अद्भुत सुकून देता है। इसके बाद हम पहुँचे चितई गोलू देवता मंदिर, जहाँ विराजते हैं पहाड़ों के न्याय के देवता गोलू देव। यहाँ लोग अपनी पीड़ा और अन्याय की अर्जियाँ मंदिर में बाँधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर घंटियाँ चढ़ाकर आभार व्यक्त करते हैं। मंदिर में टंगी हजारों घंटियाँ और अर्जियाँ इस अटूट विश्वास की गवाही देती हैं कि देवता सबकी सुनते हैं। हमारे सफर का अगला पड़ाव था जागेश्वर धाम। देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित यह प्राचीन मंदिर परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। कहा जाता है कि आदिकैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा का आध्यात्मिक आरंभ यहीं से होता है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस परिसर में सवा सौ से अधिक शिवलिंग स्थापित हैं, जहाँ पहुँचकर मन स्वतः ही शांत हो जाता है।

शाम ढलते-ढलते हमारा कारवां पहुँचा गुंजी गांव। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हम अपने होम-स्टे पहुँचे। अगली सुबह जब हम लगभग पंद्रह हजार फीट की ऊँचाई पर स्थित आदिकैलाश पहुँचे, तो सामने फैली हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं ने मानो मन को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान शिव हिमालय की गोद में विराजमान हों। ढाई किलोमीटर की पक्रिमा के दौरान पार्वती कुंड, भीम खेत और गौरीकुंड के दर्शन हुए। बर्फीली हवाओं और शांत वातावरण के बीच यह अनुभव शब्दों से परे था।

अगली सुबह हम निकले ओम पर्वत की ओर। दुर्गम रास्तों और ऊँचे पहाड़ों के बीच जब दूर बर्फ से ढकी चोटी पर प्राकृतिक रूप से बनी 'ऊँ' की आकृति दिखाई दी, तो मन श्रद्धा से भर उठा। उस क्षण केवल 'ऊँ नमः शिवाय' का जाप ही हृदय में गूंज रहा था।

ओम पर्वत के दर्शन के बाद हमारी वापसी यात्रा शुरू हुई। हम फिर पहाड़ों की ठंडक छोड़कर मालवा की धरती और 43-44 डिग्री तापमान में लौट आए। सहयात्री भाई श्रीकांत पटवा और राहुल परमार के साथ आदिकैलाश और ओम पर्वत की यह रोमांचक, आध्यात्मिक और अविस्मरणीय यात्रा हमेशा के लिए हमारे मन और स्मृतियों में बस गई।

# 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर आशा, उषा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे

## पैसा नहीं तो काम नहीं

**धार।** धार जिले के सभी विकासखण्ड के आशा, उषा कार्यकर्ता आशा पर्यवेक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर पूरे धार जिले के सभी ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता ने शुक्रवार से काम बंद कर दिया और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। घर परिवार की स्थिति ख़राब है, घर-परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। इस सम्बन्ध में वेतन लम्बे समय से नहीं मिलने को लेकर 8 मई को आशा,उषा सहयोगी संगठन की जिलाध्यक्ष संगीता मारु मोयाखेड़ा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर कलेक्टर और सीमीएचओ मुख्यालय पर ज्ञापन भी दिया गया था, चर्चा कर बताया भी गया था कि 14 मई तक वेतन नहीं निकलता है तो जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर 15 मई से जिले के समस्त आशा कार्यकर्ता,उषा आशा पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे।

आशा उषा आशा पर्यवेक्षक संगठन के इंदौर संभागीय अध्यक्ष शंकरलाल मारु ने बताया कि वेतन की मांग को लेकर धार जिले के सभी ब्लॉक में कहां पर मेडिकल ऑफिसर तो कही पर बी पी एम , बीसीएम को ज्ञापन दिया गया है । शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरने सम्बन्धित ज्ञापन सौंपा गया।

मध्य प्रदेश आशा कार्यकर्ता, उषा, आशा पर्यवेक्षक संगठन के इंदौर संभागीय अध्यक्ष शंकरलाल मारु मोयाखेड़ा ने बताया कि जिले में भी कभी पूछो तो बताते है नहीं है पेमेंट, ना कभी फोन उठाते हैं और काम करवाने के लिए जिले और ब्लॉक के अधिकारी कलेक्टर और एसडीएम की धमकी देते हैं।

# बिजली की बदहाली के खिलाफ आधी रात में चक्काजाम, नगर हित में सब नागरिक एक

**सोहागपुर।** नगर में लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था और घंटों की अघोषित कटौती एवं बदहाली के विरोध में शुक्रवार देर रात नागरिकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गत दिवस शाम 6 बजे से शुरू हुई बिजली कटौती रात 2 बजे तक जारी रही। इससे परेशान होकर भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं सैकड़ों नागरिकों ने बिजली विभाग कार्यालय के समीप पेट्रोल पंप चौराहे पर चक्का जाम कर दिया।

करीब डेढ़ घंटे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नाराज़गी जाहिर की। तहसीलदार राकेश खजूरिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों को समझाने का प्रयास किया,।लेकिन नागरिक एसडीएम एवं डीजीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बताया गया कि एसडीएम प्रियंका भल्लावी अपने मुख्यालय पर मौजूद नहीं थीं।जिसके चलते वह मौके पर नहीं पहुंच सकीं। इस बात को लेकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पीड़ितों का कहना था कि जब शहर की जनता रातभर सड़कों पर परेशान खड़ी है, तब जिम्मेदार अधिकारी मुख्यालय से नदारद हैं। स्थिति तब शांत हुई जब बिजली विभाग के डीजीएम मौके पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज ने तीखे शब्दों में नगर की चरमराई बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तत्काल सुधार की मांग की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के रवैये पर भी नाराज़गी जताई और चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा। ब्लाक भाजपा अध्यक्ष अश्विनी सरोज ने कहा कि नगर हित में हम कांग्रेस-भाजपा नहीं करते, हम सिर्फ नगर के लोगों की बात करते हैं। हमारी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। नगर के नागरिकों को यदि कोई अधिकारी अपने तानाशाही रवैये से परेशान करेगा । तो हम सब एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। जनता सड़क पर है और जिस अधिकारी के हाथ में शहर का लॉ एंड ऑर्डर है, वही मुख्यालय से गायब है।

सरकार की जनहितैषी योजनाओं पर ऐसे लापरवाह अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं। यदि अधिकारी मुख्यालय पर नहीं रह सकते तो अपना तबादला कराकर गांव चले जाएं।÷ पीड़ितों ने बिजली विभाग को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि नगर की बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। चक्का जाम में भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज, भाजपा युवा जिला उपाध्यक्ष अभिनव पालीवाल, कांग्रेस युवा नेता प्रशांत मालवीय, विजय छावड़िया (नन्नू भैय्या) पार्षद आशीष विश्वकर्मा, श्रीकांत रघुवंशी सहित भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता और नगर के सैकड़ों नागरिक मौजूद उपस्थित थे।

# श्रीमद्भागवत कथा के अवसर पर निकाली कलशयात्रा, शामिल हुए महामंडलेश्वर स्वामी अनिल आनंद महाराज जी

**(हीरालाल गोलानी )**

भोपाल। इन्द्रविहार पंचवटी कालोनी के शिव झूलेलाल मंदिर से श्री श्री सत्य अनंत माधवाय नमः विश्व सनातन धर्म - श्री महाकालेश्वर मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा,जगन्नाथ संस्कृति, भविष्य मलिका पुराण, श्री विष्णु महायज्ञ, मानव कल्याण के लिए के 15 से 21 मई को होने वाली कथा के

अवसर पर भव्य कलशयात्रा निकाली गई। इस गरिमामय कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी अनिल आनंद महाराज जी खाटूश्यामजी मंदिर सिन्धी कालोनी भोपाल शामिल हुए। शिव झूलेलाल मंदिर से निकली कलशयात्रा के प्रथम में डीजे द्वितीय में नीरजा गोलानी खूबचदानी के द्वारा निर्मित आकर्षक जगन्नाथपुरी मंदिर की आकृति को सिर लेकर चल रहे थे। बारी बारी से दोनों कालोनियों के नागरिक सिर उठाकर चल रहे थे।

इस कलश यात्रा में मातृशक्ति कलश हुई थी। वहीं गणमान्य नागरिक डांडिया नृत्य करते चल रहे थे। डीजे की धार्मिक धुनों पर मातृशक्ति एवं गणमान्य नागरिक भी झूमते नजर आ रहे थे। वहीं आयोजक पंकज खूबचदानी ने अपने सिर पर श्रीमद्भागवत पुराण लेकर चल रहे थे। इसके साथ रास्ते पर जल छिड़का जा रहा था। कलशयात्रा कालोनी के विभिन्न मार्गों पर होकर भोपाल के विख्यात भोपाल गर्ल्स स्कूल पंचवटी एयरपोर्ट रोड लालघाटी पर पहुंची। इस गरिमामय शोभायात्रा में महामंडलेश्वर स्वामी अनिल आनंद महाराज जी खाटूश्यामजी मंदिर सिन्धी कालोनी, आयोजक खूबचदानी परिवार के सदस्य सहित कई गणमान्य नागरिक एवं मातृशक्ति उपस्थित थे।भोपाल गर्ल्स स्कूल पंचवटी परिसर में उड़ीसा के कथा वाचक व्यास जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान परम पूज्य पंडित डॉ. श्री काशीनाथ मिश्र जीके मुखारविंद से होगा। कथा आज से प्रारंभ होकर 21 मई को कथा को विराम दिया जाएगा। कथा शाम 5 से 8 बजे तक होगी। उल्लेखनीय है कि जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान डॉ. काशीनाथ जी मिश्र टोरंटो कनाडा सहित भारत कई प्रान्तों में अपने मुखारविंद से कथा का आयोजन कर चुके हैं।

# स्थानीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण प्रशिक्षण संपन्न

**सोहागपुर।** जनपद पंचायत के सभा कक्ष में स्थानीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष 2026 के संबंध में बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी ने निर्धारित प्रपत्रों के सही उपयोग एवं समय सीमा में कार्य करने का निर्देश दिया गया। इस कार्यक्रम में संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्राधिकृत कर्मचारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया, दिशा-निर्देश एवं आवश्यक सावधानियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मतदाता सूची के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन तथा फोटोयुक्त मतदाता सूची को अद्यतन करने संबंधी आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं त्रुटिरहित होना लोकतांत्रिक

प्रक्रिया की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः समस्त सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ कार्य करने का आग्रह किया गया। जनपद पंचायत सोहागपुर के सभा कक्ष में, प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर राहुल तिवारी विपिन गिल्ला अमित मिश्रा संदीप कुशवाहा ने सभी संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया।

# तमाम प्रयासों के बाद भी सरकारी स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या

## लक्ष्य के मुकाबले 92.93 प्रतिशत ही नामांकन

**एस. द्विवेदी**

**बैतूल।** जिले में हर साल बच्चों के नामांकन संख्या में कमी आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक कुल 2 लाख 81 हजार 744 विद्यार्थियों के प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक 2 लाख 61 हजार 788 विद्यार्थियों का ही नामांकन हो सका है। यह लक्ष्य के मुकाबले 92.92 प्रतिशत है। आमला में 30173 आठनेर में 16858, बैतूल में 52342, भैंसदेही में 23901, भीमपुर में 25293, चिचोली में 16271, घोड़ाडोंगरी में 35056, मुलताई में 25609, प्रभातपट्टन में 16563 और शाहपुर में 19722 बच्चों का नामांकन हो पाया है। जबकि बीते साल जिलेभर के स्कूलों में प्री-प्रायमरी से 12वीं तक 2 लाख 81 हजार 744 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था। इनमें सबसे ज्यादा 57436 बच्चे बैतूल ब्लॉक में थे। इनके अलावा घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में 37350, आमला में 31113, आठनेर में 18202, भैंसदेही में 26274, भीमपुर में 27984, चिचोली में 17495, मुलताई में 27766, प्रभातपट्टन में 17299 और शाहपुर ब्लॉक में 20825 बच्चे दर्ज थे। इस साल भी विभाग द्वारा इतने बच्चों का नामांकन किए जाने का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि इस साल इतने बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है प्रवेश अभियान अभी जारी है और शेष बच्चों को स्कूलों से जोडने के लिए लगातार संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान, पलायन और प्रारंभिक कक्षाओं में अभिभावकों की कम रुचि नामांकन घटने के प्रमुख कारण हो सकते हैं।

**प्री-प्राइमरी कक्षाओं की स्थिति कमजोर-** सबसे कमजोर स्थिति प्री-प्राइमरी कक्षाओं में सामने आई है। यहां 14 हजार 888 बच्चों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 10 हजार 464 बच्चों का ही प्रवेश हुआ, जो मात्र 70.28 प्रतिशत है। भीमपुर ब्लॉक में तो हालात सबसे खराब रहे, जहां लक्ष्य के मुकाबले केवल 23.81 प्रतिशत बच्चों का नामांकन दर्ज किया गया। वहीं शाहपुर में 49.06 प्रतिशत, आठनेर में 59.55 प्रतिशत और भैंसदेही में 64.11 प्रतिशत नामांकन ही हो सका। हालांकि कक्षा 1 से 8 तक की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही। यहां 1 लाख 86 हजार 330 के लक्ष्य के मुकाबले 1 लाख 72 हजार 099 विद्यार्थियों का प्रवेश दर्ज किया गया, जो 92.36 प्रतिशत है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक कई ब्लॉकों ने लक्ष्य से अधिक नामांकन दर्ज किया। आमला में 108.33 प्रतिशत, आठनेर में 100.59 प्रतिशत और शाहपुर में 103.49 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है।

### शिक्षक और सुविधाओं की कमी भी एक बड़ा कारण

यदि जिले के सरकारी स्कूलों पर नजर डाली जाये तो सरकारी स्कूलों में प्रायमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक 93.87 प्रतिशत ही बच्चों को नामांकन हुआ है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन का लक्ष्य 188637 निर्धारित किया था, जिसके एवज में 177073 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। इसके पीछे जानकारों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में एक तो शिक्षक पर्याप्त नहीं है, कई स्कूल में एक शिक्षक को 5-5 कक्षाएं संभालना पड़ रहा है। इसके अलावा कई स्कूल भवन जर्जर है। उसमें बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर निजी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक होते है और पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होता है। जिसकी वजह से पालक सरकारी स्कूलों की बजाये निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना बेहतर समझते है। ग्रामीण क्षेत्र तक में लोग स्थानीय सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बजाए शहर के निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते है। कुछ स्कूलों के हालात तो ऐसे है, जहां महज 1 से 10 बच्चे ही है।

### नामांकन बढ़ाने किये जाते हैं कई प्रयास

सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़ सके, लेकिन शासन के तमाम प्रयासों के बाद भी सरकारी स्कूलों के हालात नहीं सुधर पा रहे है। परिणाम सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होते जा रही है। जबकि सरकार द्वारा बच्चों को स्कूल लाने के लिए स्कूल चले हम अभियान चलाया जा रहा है। घर-घर दस्तक देकर सर्वे किये जाते है। सरकारी स्कूलों में पढने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क पुस्तके, ड्रेस और आने-जाने के लिए साइकिलें वितरित की जाती है। इसके बाद भी नामांकन के मामले में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। इसे लेकर जिला कलेक्टर भी समीक्षा बैठक में नाराजगी जता चुके है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित कर लक्ष्य अनुसार प्रगति लाये।

### जिले के स्कूलों में नामांकन की स्थिति

| ब्लाक | लक्ष्य | नामांकन |
|---|---|---|
| आमला | 31113 | 30137 |
| आठनेर | 18202 | 16858 |
| बैतूल | 57436 | 52342 |
| भैंसदेही | 26274 | 23901 |
| भीमपुर | 27984 | 25293 |
| चिचोली | 17495 | 16271 |
| घोड़ाडोंगरी | 37350 | 35056 |
| मुलताई | 27766 | 25609 |
| प्रभातपट्टन | 17299 | 16563 |
| शाहपुर | 20825 | 19722 |
| कुल | 281744 | 261788 |

### इनका कहना है -

हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में नामांकन की स्थिति बेहद अच्छी है। अभी तक लक्ष्य का 98.38 प्रतिशत टारगेट हासिल किया जा चुका है। जो शेष बच गया है, उसे भी पूरा कर लिया जायेगा।

**- भूपेन्द्र वरकड़े,** जिला शिक्षा अधिकारी, बैतूल

- लक्ष्य के मुताबिक नामांकन के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे है। इसके लिए समय-समय पर बैठक भी ली जा रही है, जिसमें नामांकन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकारियों को कहा जा रहा है। उम्मीद है कि हम लक्ष्य को हासिल कर लेगे।

**- सुधीर साकेत,** डीपीसी, बैतूल

# पटाखा दुकानों और मैगजीन का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों के पालन के दिए निर्देश

**बैतूल।** कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार शुक्रवार को एसडीएम बैतूल डॉ. अभिजीत सिंह ने एसडीओपी बैतूल सुनील लाटा के साथ बैतूल क्षेत्र स्थित अनुज्ञाधारी मैगजीन एवं फायर वर्क्स पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान एवं गोदाम में पटाखों के भंडारण, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा आवश्यक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान दुकान के लाइसेंस एवं अनुमति पत्रों का परीक्षण किया गया। साथ ही अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं उनकी वैधता की जांच की गई। अधिकारियों ने सुरक्षित भंडारण व्यवस्था, निर्धारित सुरक्षा मानकों के पालन, विद्युत व्यवस्था तथा आग से बचाव संबंधी उपायों का भी निरीक्षण किया। एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्टॉक एरिया के चारों ओर बाउंड्री वॉल को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। मैगजीन परिसर के आसपास मौजूद सूखी झाड़ियों एवं घास की नियमित साफ-सफाई कराने को कहा, ताकि आग लगने जैसी घटनाओं की संभावना को रोका जा सके। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति एवं अग्निशमन कार्य के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, परिसर में सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा अग्नि सुरक्षा उपकरणों का नियमित परीक्षण एवं रख-रखाव करने के निर्देश भी संबंधित संचालकों को दिए गए।

# फव्वारा चौक पर रास्ते की भूमि पर निर्माण रुका, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लगाई रोक

## जनसुनवाई में शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन, तहसीलदार व थाना प्रभारी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

**बैतूल।** मुलताई नगर के व्यस्ततम क्षेत्र फव्वारा चौक पर मुख्य मार्ग से लगी नगर पालिका सडक़ की भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। जनसुनवाई में शिकायत सामने आने के बाद तहसीलदार डॉ. संजय कुमार बरैया, थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार, राजस्व अमला तथा नगर पालिका टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि विवेकानंद वार्ड स्थित फव्वारा चौक के सामने मुख्य मार्ग से लगी भूमि पर रतन सिंह द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। शिकायतकर्ता हरप्रीत खुराना ने जनसुनवाई में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि निर्माण सार्वजनिक मार्ग के लिए दर्ज भूमि पर किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू की।

### सीमांकन के लिए गठित हुआ जांच दल

मामले की शिकायत के बाद तहसीलदार न्यायालय द्वारा सीमांकन और जांच के लिए विशेष राजस्व दल गठित किया गया था। जांच दल में राजस्व आरआई नजूल अशोक राठौर, आरआई शिवकुमार चौरासे, पटवारी सोहबत धुर्वे तथा पटवारी आशीष गामड़ शामिल थे। जांच दल ने फव्वारा चौक स्थित नजूल भूमि, सीट नंबर-21 के भूखंड क्रमांक 87/2, क्षेत्रफल 229.95 वर्गमीटर का मौका निरीक्षण किया। अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि की नपाई कर पंचनामा तैयार किया गया।

### प्रशासन बोला- न्यायालय में मामला लंबित, तब तक नहीं होगा निर्माण

मौके पर पहुंचे तहसीलदार डॉ. संजय कुमार बरैया ने राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण किया तथा जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित भूमि स्वामी को स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज मार्ग क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाए। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने भी दोनों पक्षों को आपसी सहमति और कानून के दायरे में रहकर विवाद का समाधान निकालने की समझाइश दी। उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा थाना मुलताई में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी।

## शॉर्ट न्यूज

### रायसेन जिले की 2,43,683 बहनों के खाते में 35 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित

**रायसेन (निप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश के साथ ही रायसेन जिले की 2,43,683 बहनों के खातों में 35 करोड़ 83 लाख 56 हजार 900 रूपये की राशि अंतरित की।

### बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर धारा 136 में होगी कार्रवाई

**रायसेन (निप्र)।** विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि यदि बिजली के मीटर में अनावश्क छेड़छाड़ पाई जाती है तो ऐसा करने वालों के विरूद्ध धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी। कंपनी का कहना है कि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉल सेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑन लाइन वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा उपाय यूपीएवाय ऐप या बिजली वितरण केन्द्र, जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण की पुख्ता व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें 3 वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है।विद्युत अधिनियम. 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि ष्अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइनए सामग्री या मीटर को हटाएगा या अन्यत्र जगह लगाता हैए चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहींए तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध कहा जाएगा और वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

### दिव्यांगों को बस किराये में 50 प्रतिशत छूट

**सीहोर (निप्र)।** राज्य शासन ने प्रदेश की सभी प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को 50 प्रतिशत छूट देने के निर्देश दिये हैं। दिव्यांग व्यक्ति को यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर यह छूट मिल जायेगी।परिवहन आयुक्त द्वारा सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं। दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगजन सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के रूप में केन्द्र या राज्य शासन द्वारा जारी यूनीक डिसऐबिलिटीज आई.डी. कार्ड प्रस्तुत करने पर किराये में 50 प्रतिशत छूट का लाभ दें।केन्द्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यूनीक आई.डी. फॉर पर्सन विद डिसऐबिलिटीज (यूडीआईडी) प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड दिये जा रहे हैं। कार्ड के माध्यम से दिव्यांग केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड निर्माण में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है।

### फायर सेफ्टी सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

**बैतूल (निप्र)।**अपर मिशन संचालक भोपाल के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय बैतूल एवं जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में 4 मई से 10 मई तक फायर सेफ्टी सप्ताह अंतर्गत जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला चिकित्सालय बैतूल में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ जगदीश घोरे के निर्देशन में फायर सेफ्टी सप्ताह अंतर्गत 4 मई 2026 को शपथ ग्रहण एवं नर्सिंग छात्राओं को फायर सेफ्टी प्रशिक्षण दिया गया। वहीं 5 मई को जिला बैतूल की क्वालिटी टीम द्वारा संस्था का आंतरिक फायर सेफ्टी मूल्यांकन किया गया। फायर सेफ्टी पोस्टर प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिता 7 मई को आयोजित कर प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इसके अलावा 8 एवं 10 मई को अस्पताल में कार्यरत सभी अधिकारियों , कर्मचारियों के लिए जिला होमगार्ड बैतूल एवं फायर सेफ्टी कंसलटेंसी एजेंसी द्वारा फायर सेफ्टी एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। साथ ही फायर सेफ्टी सप्ताह अंतर्गत शपथ ग्रहण एवं जागरूकता गतिविधियां जिले की विभिन्न संस्थाओं में आयोजित की गई। जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में क्वालिटी असेसर कविता सिंह, एमएच कोर्डिनेटर श्रीमती सविता चढ़ोकार, सीनियर नर्सिंग ऑफीसर श्रीमती शोभा बानखेड़े एवं स्टाफ मौजूद रहा।

### सीहोर जिले की 2,40,252 बहनों के खाते में 35 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित

**सीहोर (निप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले की 2,40,252 बहनों के खातों में 35 करोड़ 38 लाख 59 हजार 900 रूपये की राशि अंतरित की।

# वैज्ञानिक भंडारण से गरीबों तक राशन पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया से रूबरू हुए युवा

**युवाओं ने सरकारी भंडार गृह रायसेन बम्होरी में समझी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जमीनी व्यवस्था**

**रायसेन (निप्र)।** युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित ''मेरा युवा भारत'' जिला रायसेन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रथम दिवस पर युवाओं ने सरकारी भंडार गृह रायसेन का शैक्षणिक भ्रमण कर खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया को नजदीक से समझा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओंए खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तथा वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली से व्यावहारिक रूप से परिचित कराना रहा।

कार्यक्रम के दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी श्री राजू कातुलकरएश्रीमती संगीत सहायक आपूर्ति अधिकारी, श्री यशपाल मालवीय ने प्रतिभागियों को भंडारण व्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षा मानकों एवं पीडीएस संचालन की विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक गेहूं, चावल, नमक सहित अन्य आवश्यक खाद्यान्न उचित मूल्य पर पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए खाद्यान्नों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण अत्यंत आवश्यक होता है। युवाओं को सरकारी भंडार गृह में खाद्यान्न



आगमन से लेकर अंतिम वितरण तक की प्रत्येक प्रक्रिया का अवलोकन कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले वाहनों की गेट एंट्री की जाती है, जिसके बाद खाद्यान्न से भरे ट्रकों का वजन किया जाता है। इसके बाद गुणवत्ता परीक्षण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया अपनाई जाती हैए जिसमें विशेष रूप से गेहूं की गुणवत्ता, नमी, स्वच्छता एवं भंडारण योग्य स्थिति की जांच की जाती है। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि खाद्यान्नों को वैज्ञानिक तरीके से स्टैकिंग कर सुरक्षित रखा जाता है ताकि नमी, फफूंदी एवं कीटों से बचाव हो सके। भंडारण केंद्रों में प्रत्येक सात दिन के अंतराल पर कीटनाशक स्प्रे एवं नियमित निरीक्षण किया जाता हैए जिससे खाद्यान्न सुरक्षित एवं उपयोग योग्य बना रहे। अधिकारियों ने बताया कि रायसेन जिले की पीडीएस दुकानों को यहीं से खाद्यान्न आवंटित किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशन दुकानों तक सामग्री पहुंचाई जाती है। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण प्रणाली से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गंभीरता से समझा तथा अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त की। प्रतिभागियों ने कहा कि इस प्रकार के अनुभवात्मक कार्यक्रम युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझने और शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक बनाने में अत्यंत उपयोगी हैं। इस अवसर पर M4 Bharat रायसेन की डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती मोनिका चौधरी तथा युवा समाज सेवी श्री विशाल सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिलता है, जिससे उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक समझ का विकास होता है।

कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने युवाओं से खाद्य सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जनसेवा से जुड़ी व्यवस्थाओं को समाज तक पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। M4 Bharat द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं को शासन की व्यवस्थाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

### स्वरोजगार स्थापित करने संत रविदास स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

**रायसेन (निप्र)।** अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शासन द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले में संत रविदास स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 8वीं कक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं तथा महिलाओं को लाभान्वित करने 40 इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आवेदक स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से एक लाख रू से 50 लाख रू तक का उद्योग इकाई और सेवा इकाई के लिए एक लाख रू से 25 लाख रू तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना के तहत स्वीकृत इकाई लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक ब्याज अनुदान देय होगा। संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष तक की आयु के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

## जिले की 271319 लाडली बहनों के खातों में 40 करोड़ रुपये अंतरित

**विदिशा (निप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा आथ बुधवार 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में माह मई 2026 की आर्थिक सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की है। इस अवसर पर विदिशा जिले की 2 लाख 71 हजार 319 लाडली बहनों के खातों में लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की हुई है।

इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण विदिशा के एनआईसी वीसी कक्ष में भी किया गया। यहां कार्यक्रम में उपस्थित विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण व जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया के अलावा हितग्राही लाडली बहनाएं मौजूद रहीं। उपस्थित सभी के द्वारा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और सुना गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांस्बा ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना




अंतर्गत विदिशा जिले की पात्र महिलाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ उनके परिवारों को भी आर्थिक मजबूती मिल रही है। जिले के विभिन्न जनपद एवं नगरीय निकायों की लाभार्थी महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। इनमें जनपद पंचायत बासौदा की 40,483, ग्यारसपुर की 24,298, कुरवाई की 27,305, लटेरी की 25,547, नटेरन की 33,159, सिरोंज की 36,572 तथा विदिशा की 29,330 महिलाएं शामिल हैं।

वहीं नगरीय निकायों में नगरपालिका गंजबासौदा की 11,949, नगरपालिका सिरोंज की 8,747, नगरपालिका विदिशा की 25,578, नगर परिषद कुरवाई की 2,988, नगर परिषद लटेरी की 3,335 तथा नगर परिषद शमशाबाद की 2,028 महिलाओं के खातों में राशि अंतरित की जाएगी।

## पंजीकृत श्रमिकों के लिए संजीवनी बनीं शासकीय योजनाएं

**रायसेन (निप्र)।** प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं।

श्रम विभाग और विभिन्न बोर्ड्स के माध्यम से अब श्रमिकों को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हर कदम पर आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। इनमें प्रसूति सहायता 16 हजार, बेटियों के विवाह के लिये अनुदान 49 हजार रूपये और 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क चिकित्सा लाभ (आयुष्मान भारत) शामिल है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के बच्चों को वैश्विक स्तर की शिक्षा देने के लिए श्विदेश अध्ययन योजनाश् के तहत 40 हज़ार डॉलर तक की सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही अधिकतम 10 हजार यू.एस. डॉलर प्रतिवर्ष बतौर वार्षिक निर्वाह भत्ता भी प्रदान किया जाता है। राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 हज़ार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्रमिकों के आवास निर्माण के लिए एक लाख रूपये तक, ई-स्कूटर खरीदी के लिए 40 हजार रूपये तक और औजार अनुदान भी सीधे उनके बैंक खातों ष्क्ठ्ठ में भेजा जा रहा है। पात्र श्रमिक निर्धारित समय-सीमा के भीतर श्श्रम सेवा पोर्टलश् या श्लोक सेवा केंद्रश् के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

## ग्रामीणों को इलाज के लिए परेशान न होने पड़े : कलेक्टर डॉ सोनवणे

**बैतूल (निप्र)।** कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को चिचोली विकासखंड के ग्राम चिरापाटला का भ्रमण कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचे और ग्रामीणों को उपचार के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरापाटला में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण कर बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन एवं गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच संबंधी रजिस्टर और प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। उन्होंने नेत्र जांच एवं अस्थि रोग जांच व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण कर शिविर संचालन की गुणवत्ता परखी।

उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्र में नियमित एवं सुचारू रूप से डिलेवरी सेवाएं संचालित हों तथा चिकित्सक और स्टाफ केंद्र पर उपस्थित रहें, ताकि ग्रामीणों को समय पर उपचार मिल सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने एंटीवेनम, आयरन सिरप सहित आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि उपलब्ध दवाओं का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि दवाएं उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग न होने से मरीजों को अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर न लगाना पड़े, जिससे उनकी स्थिति और अधिक गंभीर हो। इस दौरान ग्राम अजई निवासी रमेश कन्हैया ने दिव्यांगता कार्ड नहीं बनने की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने मेडिकल बोर्ड के माध्यम से शीघ्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के सभी विकासखंडों में प्रत्येक माह में एक बार मेडिकल बोर्ड आयोजित करने के निर्देश भी दिए, ताकि दिव्यांगजनों को सुविधा मिल सके। इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम पंचायत चिरापाटला के सभाहॉल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद पंचायत एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तीन दिवस के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व से संचालित जल योजनाएं बंद न हों और सभी घरों तक नियमित पानी पहुंचे। निर्माणाधीन सड़क के कारण क्षतिग्रस्त हुई नल-जल योजना के निराकरण के निर्देश भी जनपद सीईओ को दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने स्वीकृत हैंडपंप कार्यों में बिना अनुमति स्थल परिवर्तन पर नाराजगी जताते हुए संबंधितों से वसूली की चेतावनी दी। उन्होंने फौती नामांतरण, अभिलेख दुरुस्ती, राशन कार्ड, पीएम आवास सहित विभिन्न शिकायतों पर त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए तथा पटवारियों को राजस्व प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण करने की सख्त हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ग्रामीणों से ली। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में शून्य पंजीयन पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

## कलेक्टर के प्रयासों से विद्यालयों में बढ़ीं सुविधाएं

**सीएसआर सहयोग से जिले के 10 शासकीय विद्यालयों को मिला नया फर्नीचर**

**विदिशा (निप्र)।** विदिशा जिले में विद्यार्थियों को बेहतर एवं सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रभावी प्रयास कर रहा है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के सतत प्रयासों एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप जिले के शासकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत हुडको एवं बीपीसीएल बीना ऑयल रिफाइनरी के सहयोग से जिले के अनेक विद्यालयों को डबल डेस्क फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है।

इस महत्वपूर्ण पहल के तहत लटेरी विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंदपुर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उनारसी कलां, शासकीय हाई स्कूल जावती तथा बासौदा एवं ग्यारसपुर विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल खजूरी और शासकीय हाई स्कूल इंदरवास को प्रत्येक विद्यालय में 50-50 डबल डेस्क फर्नीचर सेट प्रदान किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को बैठने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी तथा कक्षाओं में अध्ययन का वातावरण अधिक व्यवस्थित



और अनुकूल बनेगा। इसके अतिरिक्त लटेरी विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरवास, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कालादेव एवं शासकीय माध्यमिक शाला कोलुआ पठार को प्रत्येक विद्यालय में 100-100 डबल डेस्क फर्नीचर सेट उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं विदिशा विकासखंड के शासकीय माध्यमिक शाला स्टेशन एरिया को भी 50 डबल डेस्क फर्नीचर सेट प्रदान किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से जिले के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। नवीन फर्नीचर उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा, जिससे उनकी अध्ययन गतिविधियों में सकारात्मक सुधार आएगा। विद्यालय प्रबंधन समितियों, शिक्षकों एवं स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

### बुधनी तहसील में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य हुआ पूरा, एसडीएम और तहसीलदार से पूरी टीम को दी बधाई

**सीहोर (निप्र)।** कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधनी तहसील में मकान सूचीकरण का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इस सराहनीय उपलब्धि के लिए बुधनी एसडीएम श्री दिनेश सिंह तोमर और तहसीलदार श्री ललित सोनी ने सभी सुपरवाइजर्स, प्रगणक और पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कम समय में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति न केवल अन्य सुपरवाइजर्स और प्रगणकों के लिए प्रेरणास्रोत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यदि जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य किया जाए तो निर्धारित समयसीमा के भीतर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

## जन-कल्याण के लिए जिला प्रशासन व उद्योगपतियों ने मिलाया हाथ

**रायसेन (निप्र)।** एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, मण्डीदीप के सभागार में आज 13 मई को कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में उद्योगपतियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में औद्योगिक समस्याओं के निराकरण और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (ष्टस्क्र) के माध्यम से जन-कल्याणकारी कार्यों को गति देने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान उद्योगपतियों ने मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। बैठक में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समाधान के लिए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ''भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा'' के



सकारात्मक संदेश को साझा किया। उन्होंने आग्रह किया कि उद्योग जगत भविष्य में गैस, डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए नवाचारी ऊर्जा विकल्पों पर ध्यान दें, जिससे देश ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही ष्टस्क्रमद के माध्यम से सामाजिक सरोकार के कार्य और जिले के विकास में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर जोर दिया। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने शिक्षा, शासकीय स्कूलों में 12वीं कक्षा के लिए स्मार्ट क्लास की स्थापना और प्राथमिक स्कूलों में फर्नीचर व वाटर प्यूरीफायर की उपलब्धता, स्वास्थ्य और पोषण तथा अति-कुपोषित बच्चों के लिए 6 ह्रष्ट भवनों में ्रष्ट लगाना और आंगनवाड़ी केंद्रों में सोलर सिस्टम की स्थापना। साथ ही पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में जिले में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण और प्रधानमंत्री आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना रहा। एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज के संरक्षक श्री राजीव अग्रवाल ने कलेक्टर श्री विश्वकर्मा को वर्तमान में चल रहे ष्टस्क्रकार्यों से अवगत कराया और प्रस्तावित जनकल्याणकारी कार्यों हेतु आश्वासन दिया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, एसडीएम गौहरगंज श्री चंद्रशेखर श्रीवास्तव, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्री सिद्धार्थ खरे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति उपस्थित रहे।

# उज्जैन की जनता सिंहस्थ के कार्यों में सहयोग कर पेश कर रही हैं नई मिसाल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

## मुख्यमंत्री ने हरसिद्धि पाल से रामघाट मार्ग चौड़ीकरण कार्य का किया निरीक्षण

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 के लिए श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के आवागमन एवं सुविधाएं बढ़ाने के लिए घाटों एवं मार्गों के चौड़ीकरण कार्य किए जा रहे है। सरकार द्वारा सभी कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। सिंहस्थ के लिये सभी कार्य इस तरीके से किए जा रहे है कि पौराणिक और धार्मिक नगरी उज्जैन को लंबे समय तक उनका लाभ प्राप्त हो। उज्जैन के जनप्रतिनिधि, सभी धर्म के अनुयायी और नागरिक विकास कार्यों का समर्थन कर रहे है और सहयोग प्रदान कर देश के लिए एक नई मिसाल बन रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को उज्जैन में रामघाट पहुंचकर हरसिद्धि पाल से राम घाट मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत कार्य तेजी गति, गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें।

**होमगार्ड द्वारा आयोजित बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का अवलोकन किया**-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरसिद्धि पाल से रामघाट मार्ग चौड़ीकरण के निरीक्षण के बाद होमगार्ड द्वारा आयोजित बाड़ बचाव प्रशिक्षण का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होमगार्ड जवानों की हौसला अफजाई की। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री संतोष कुमार जाट ने जानकारी दी कि होमगार्ड द्वारा 250 होमगार्ड जवानों को बाढ़ बचाव के लिए डीप डाइविंग, नाविकों, स्विमिंग, लाइफ जैकेट के उपयोग का तरीका, आपदा और बाढ़ बचाव सामग्री का उचित प्रयोग, अंडर वॉटर रेस्क्यू और सर्फेस वॉटर रेस्क्यू का 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

## ओंकारेश्वर-ममलेश्वर विकास प्राधिकरण बनेगा

मोहन यादव सरकार जल्दी ही ओंकारेश्वर ममलेश्वर विकास प्राधिकरण बनाएगी। इस विकास प्राधिकरण के जरिए ओंकारेश्वर के विकास को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके अलावा पीएचई विभाग के शहरी क्षेत्र के अमले को नगरीय निकायों में मर्ज किए जाने पर भी सरकार जल्द फैसला करेगी। सरकार ने प्रदेश की तीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज को भोपाल, उज्जैन, जबलपुर में विभाजित करने का भी फैसला किया है। साथ ही चित्रकूट और ओरछा में पर्यटन विकास के प्रस्ताव मंजूर करने के साथ राम वन गमन पथ के काम में भी तेजी लाने का निर्णय हुआ है।

### आदि उत्सव जनजातीय गौरव, संस्कृति और उद्यमिता का है अद्भुत संगम : सीएम यादव

# जनजातीय परम्पराओं को किया जा रहा है संरक्षित

**भोपाल (नप्र)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 'आदि उत्सव' जैसे आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विरासत से विकास के संकल्प को पूरा करने का माध्यम भी हैं। जनजातीय संस्कृति से जुड़ी वैभवशाली परम्पराओं के प्रदर्शन और संरक्षण में ऐसे उत्सवों का विशेष महत्व है। पिछले एक दशक से यह आयोजन जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और वैभवशाली विरासत को सहेजने के साथ आधुनिक उद्यमिता के माध्यम से उसे नए आयाम देने का सशक्त मंच बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह उत्सव ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो होली और दीपावली एक साथ आ गई हों। उन्होंने मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, उमरिया और छिंदवाड़ा अंचल से पहुंचे गोंड एवं बैगा समाज के भाई-बहनों का स्वागत करते हुए आयोजन की भव्यता की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंडला जिले में रामनगर में हुए 'आदि उत्सव' को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंडला का गोंड आर्ट, कर्मा, सैला और रीना नृत्य तथा बैगा समाज का परधोनी नृत्य जनजातीय संस्कृति की सुंदर अभिव्यक्ति हैं। इन परंपराओं को संरक्षित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कोदो-कुटकी सहित अन्य मोटे अनाजों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए विशेष अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह उत्सव जनजातीय महापुरुषों और वीर नायकों ही नहीं गौंड और अन्य जनजातीय बंधु हिस्सा ले रहे हैं। आदि शिल्प में उद्यमियों और शिल्पियों का संगम भी हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजाति बोली और परंपराओं को हमें अगली पीढ़ी तक ले जाना है।

बिरसामुंडा, रानी दुर्गावती, टंट्याभील, राजा शंकरशाह, कुंवर रघुनाथशाह, दलपतशाह की शौर्य गाथाओं का स्मरण कराने वाला प्रेरणादायी मंच भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़ने और जनजातीय महापुरुषों के वंशजों का सम्मान करने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। यह आयोजन जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

**आदि उत्सव में हुआ है शिल्पियों का संगम**- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गत एक दशक से आदि उत्सव का आयोजन हो रहा है जो प्रशंसनीय है। आदि उत्सव में बैगा जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्र भी यहां उपयोग में लाए गए हैं। साथ ही कर्मा सेला, लोक नृत्य की छटा बिखरी है। श्रीअन्न का उत्सव भी मनाया जा रहा है। प्रदेश में कोदो कुटकी के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजाति समाज के नायक भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, टंट्या मामा, रघुनाथ शाह, भभूत सिंह आदि के सम्मान के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें ऐसे जनजाति नायकों के जन्म स्थल और कर्म स्थल पर कैबिनेट बैठक और अन्य आयोजन किए गए हैं।

### जनजातियों के लिए बढ़ाया है बजट

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए 47 हजार 425 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। तेंदूपत्ता संग्रह कार्य का लाभ जनजाति समाज को मिल रहा है। पीएम जनमन और धरती आबा अभियान से जनजातियों का हित संवर्धन हुआ है। वन धन केंद्रों के माध्यम से भी जनजातीय वर्ग लाभान्वित हो रहा है। अधोसंरचना विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं। आकांक्षा योजना के क्रियान्वयन और सांदीपनि एवं एकलव्य विद्यालयों से जनजाति समाज के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। सिकल सेल जैसे रोगों के नियंत्रण की पहल भी की गई है।

### गोंडवाना गौरव को नई पहचान दे रहा 'आदि उत्सव'

#### केन्द्रीय मंत्री ओरांव

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओरांव ने कहा कि गोंडवाना राजवंश के इस ऐतिहासिक महल का जीर्णोद्धार कराने के बाद वर्ष 2016 से लगातार यह आदि उत्सव आयोजित किया जा रहा है। जनजातीय गौरव को सम्मान देने की पहल सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जब 1999 में उन्होंने पहली बार जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया। मंडला के इस महल के जीर्णोद्धार के लिए मंत्रालय ने 1.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन, आहार अनुदान, विभिन्न छात्रवृत्तियाँ, जनजातीय बच्चों की उच्च शिक्षा जैसे अनेक काम जनजातीय समाज के कल्याण के लिए किये जा रहे हैं।

### आदि उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर बना रहा विशिष्ट पहचान

#### मंत्री श्रीमती उइके

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके ने कहा कि रामनगर का 'आदि उत्सव' अब केवल क्षेत्रीय आयोजन नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और गौरव के प्रतीक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत गोंडी बोली में करते हुए जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया। आज यह आयोजन एक बड़े उत्सव के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसमें जनजातीय संस्कृति, लोक कला, परंपराओं और इतिहास का भव्य प्रदर्शन किया जा रहा है।

### उत्सव भावी पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम

#### सांसद कुलस्ते

सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि यह आयोजन जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर आज तक राज परिवार, पंडा, पुजारी एवं भूमका समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने जनजातीय विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर प्रदेश तथा देश के अन्य हिस्सों से आए विभिन्न राज परिवार के सदस्य, जनजातीय गौरव की जानी-मानी हस्तियाँ सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे जनजातीय वर्ग के लोग भी मौजूद रहे।

# मंदिर है भोजशाला, फैसले के बाद रोने लगे हिंदू याचिकाकर्ता

### किन सबूतों ने हिंदुओं का पक्ष किया मजबूत

**धार (नप्र)।** हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि यह पूरा मंदिर है। साक्ष्यों के आधार पर पूरा क्षेत्र हिंदू मंदिर है। मुसलमानों से कहा है कि कलेक्टर से मिलकर अपने लिए अन्य स्थान चिह्नित करें। केंद्र को आदेश दिया है कि लंदन से लाकर वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करें। गोपाल शर्मा ने कहा कि यह मंदिर था और मंदिर है। यह फैसला उनलोगों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इसके लिए शहादत दी है। इसके बाद गोपाल शर्मा भावुक हो गए।

### 700 साल पुराने प्रकरण का अंत

अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने 700 साल पुराने प्रकरण को विराम दिया है। साथ ही यह तय किया है कि भोजशाला एक मंदिर है। राजा भोज द्वारा स्थापित यह एक मंदिर है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भोजशाला एक मंदिर है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि जो साक्ष्य रखे गए हैं, इसके बाद न्यायालय ने तय किया है कि यह एक सरस्वती मां का मंदिर है। एएसआई की रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट हो गया है कि यह मंदिर है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसे हिंदुओं को सौंपा जाए। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वे लोग चाहें तो सरकार को आवेदन दे सकते हैं। सरकार उनके आवेदन पर विचार करेगी कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए कोई अलग जगह दी जाए या न दी जाए। माननीय न्यायालय ने लंदन से मूर्ति वापस लाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार आगे कदम उठाएगी।

### ये सबूत रहे अहम

एडवोकेट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट से यह साफ था कि इमारत 11वीं सदी की बनी है। हवनकुंड भी ईंटों का बना हुआ है। ईंटें भी 11वीं सदी की हैं। इमारत का स्वरूप मंदिरों के रूप में हैं। अब यह तय हो गया है कि यह मंदिर है। ऐसे में यहां नियमित रूप से पूजा होगी। अब यहां किसी प्रकार की नमाज नहीं होगी। सिर्फ हिंदू पद्धति से पूजा होगी।

**सच की जीत हुई है- हिन्दू समाज**- कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर का धार्मिक स्वरूप तय कर दिया है। वहीं, इस फैसले के बाद धार में जश्न का माहौल है। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि सच की जीत हुई है।

### भावुक हो गए याचिकाकर्ता

वहीं, याचिकाकर्ता गोपाल शर्मा अपनी बात कहते-कहते भावुक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सालों की तपस्या का फल है। हिंदू संगठन के लोग भोजशाला परिसर में आज से ही नियमित पूजा की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी एएसआई को है। मुस्लिम पक्ष का दावा पूरी तरह से खारिज हो गया है। इस फैसले के बाद हाईकोर्ट के बाहर जश्न का माहौल था।

## पुलिस सुरक्षा के बीच नमाज के थोड़ी देर बाद आया हाईकोर्ट का फैसला

### भोजशाला परिसर में अब नहीं होगी जुमे की नमाज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार स्थित भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया है। शुक्रवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने

फैसला सुनाया है। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर पर नमाज की इजाजत दी गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब यहां जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी।

## जय श्रीराम के नारे, हाथों में ध्वज, जमकर बांटी मिठाई

भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला आते ही जश्न शुरू हो गया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भोजशाला परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोगों ने एक दूसरे को मिठाई और लड्डू खिलाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हिन्दू पक्ष के जश्न को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था कड़ी कर दी है। धार के हर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।

**ध्वज लेकर निकले लोग**- हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बड़ी संख्या में लोग हाथों में पताका और ध्वज लेकर मंदिर परिसर के बाहर जमा हो गए हैं। इस दौरान लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और जमकर नारेबाजी की। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल, भोजशाला के मेन गेट पर बैरिकेड्स लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। इसके बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

# भोजशाला के 188 स्तंभों की 'मौन गवाही' बनी सबसे बड़ा सबूत

धार की भोजशाला को हिन्दू मंदिर मानते हुए इंदौर हाईकोर्ट के अहम फैसले में एएसआई की रिपोर्ट सबसे अहम रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट को आधार मानकर ही कोर्ट ने भोजशाला विवाद को मंदिर करार दिया है। बता दें कि फैसले में अहम कड़ी बनकर सामने आई रिपोर्ट में भोजशाला परिसर के वो 188 मूल आधार स्तंभ जिनमें 106 मुख्य स्तंभ और 82 अर्धस्तंभों फैसले का मुख्य आधार बने, जिन पर हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक, देवी-देवताओं की आकृतियां और मंदिर शैली की नक्काशी मिलने का दावा किया गया। इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।

मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद में एएसआई की 2024 सर्वे रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। रिपोर्ट के अनुसार परिसर में कुल 106 मुख्य स्तंभ और 82 अर्धस्तंभ मौजूद हैं। इनमें से कई स्तंभों पर हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह, देवी-देवताओं की आकृतियां और पारंपरिक मंदिर शैली की नक्काशी पाई गई।

### स्तंभों पर क्या वास्तुकला मिली थी ?

एएसआई रिपोर्ट में कहा गया कि इन स्तंभों पर कीर्तिमुख, नागबंध और अन्य प्राचीन मंदिर वास्तुकला से जुड़े डिजाइन बने हुए हैं। साथ ही कई स्तंभों पर मानव और पशुओं की आकृतियां भी मिलीं, जिन्हें बाद में क्षतिग्रस्त किए जाने के संकेत मिले हैं। एएसआई रिपोर्ट के अनुसार, करीब 1265 ईस्वी में मस्जिद निर्माण के दौरान पुराने हिंदू मंदिरों के स्तंभों और मलबे का पुनः उपयोग किया गया था। यही तथ्य हिंदू पक्ष की दलीलों का बड़ा आधार बने। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कई स्तंभों पर भगवान गणेश ब्रह्मा, नृसिंह और भैरव जैसी मूर्तियों की नक्काशी दिखाई दी, जिन्हें हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का प्रमुख प्रमाण बताया।

### महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए फैसला सुनाया

हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए फैसला सुनाया। फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने खुशी जताई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

### भोजशाला पर एएसआई रिपोर्ट की मुख्य बातें

● एएसआई सर्वे रिपोर्ट में बनी भोजशाला फैसले का मुख्य आधार ● रिपोर्ट में भोजशाला में 188 आधार स्तंभों का उल्लेख ● परिसर में 106 मुख्य स्तंभ और 82 अर्धस्तंभ मौजूद हैं ● कई स्तंभों पर हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह और नक्काशी पाई गई ● स्तंभों पर कीर्तिमुख, नागबंध और पारंपरिक मंदिर शैली की आकृतियां मिलीं ● रिपोर्ट में दावा, मस्जिद निर्माण में पुराने मंदिर के स्तंभों और मलबे का पुनः उपयोग ● कई पिलर पर गणेश नृसिंह और भैरव जैसी मूर्तियों की नक्काशी मिली ● सर्वे के दौरान मानव और पशुओं की आकृतियां भी मिलीं, जिन्हें क्षतिग्रस्त बताया गया

### जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी जिन्होंने 700 साल पुराने भोजशाला विवाद पर सुनाया फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला पर अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को दोपहर ढाई बजे फैसला पढ़ना शुरू किया था।

**जस्टिस विजय शुक्ला**- जस्टिस विजय शुक्ला का जन्म 28 जून 1964 को हुआ था। उन्होंने 27 सालों तक एमपी हाईकोर्ट में वकालत की है। 27 मार्च 1987 में वह बार काउंसिल के सदस्य बने थे। 1994 से 1998 तक सरकारी अधिवक्ता के रूप में और 2007 से 2009 तक उप महाधिवक्ता के रूप में काम किया है। वहीं, 13 अक्टूबर 2016 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 17 मार्च 2018 को स्थानीय न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है।

**जस्टिस आलोक अवस्थी** - जस्टिस आलोक अवस्थी का जन्म 23 अक्टूबर 1969 को हुआ है। वह 30 जुलाई 2025 को एमपी हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं। 22 अक्टूबर 2031 को रिटायर हो जाएंगे। वह लोअर कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे हैं।